वर्ष-10//अंक-4//जनवरी 2022
ISSN 2454–5805
₹20/-

आम आदमी पत्रिका®

एक आम इंसान की सोच

RNI NO.: CHHHIN/2013/50684

बिना रुके बढ़ेंगे हम

» 6

नए साल में नया काम
कम होगी दूरियां

» 12

चार चिन्हारी छत्तीसगढ़ के लिए गेम चेंजर

» 22

कुपोषण से
जीत रहे जंग

www.aamaadmi.in

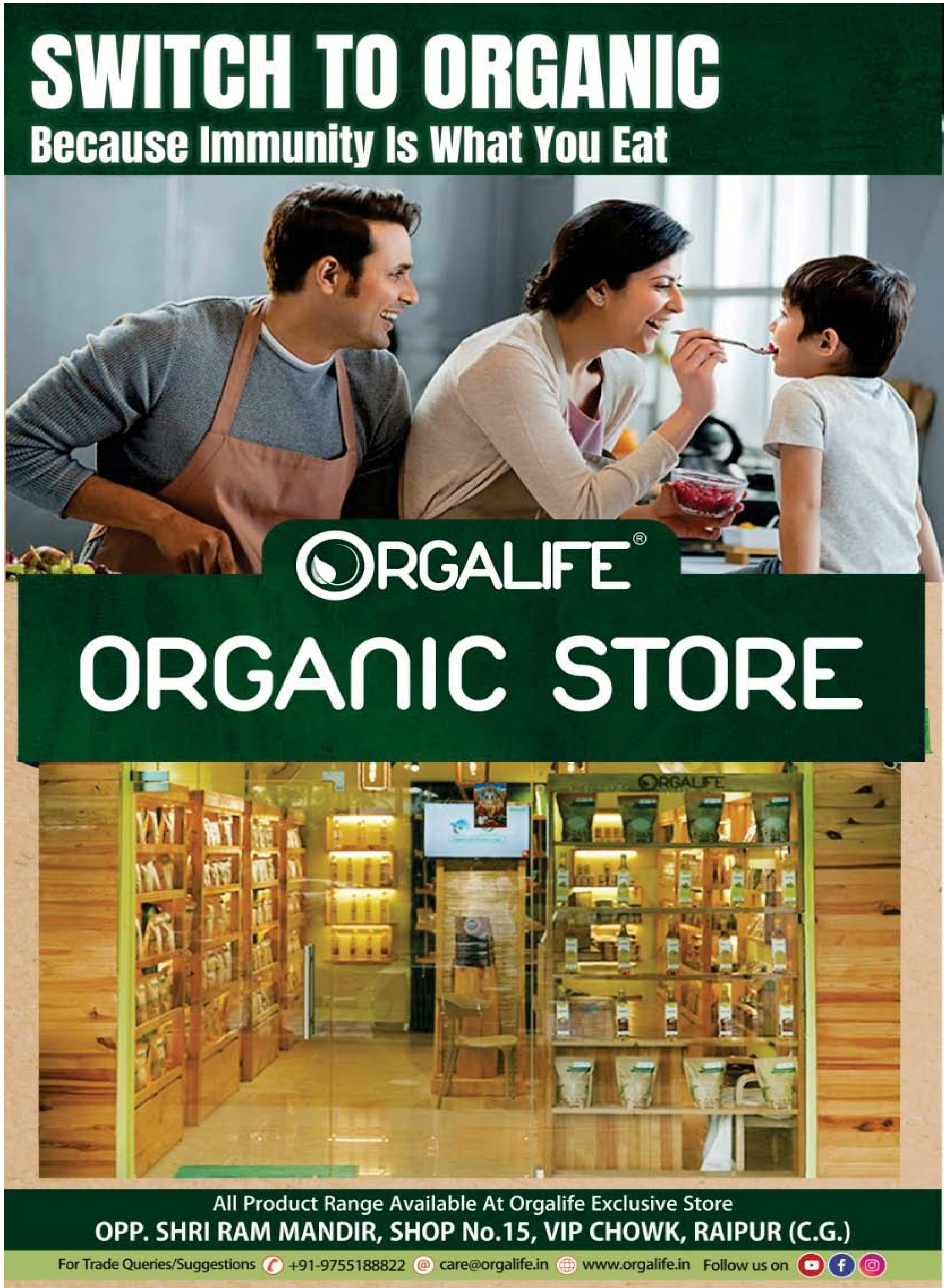

आम आदमी पत्रिका

वर्ष-10//अंक-4//जनवरी 2022

प्रबंध संपादक	: उमेश के बंसी
सर्कुलेशन इंचार्ज	: प्रकाश बंसी
रिपोर्टर	: नेहा श्रीवास्तव
कंटेंट राईटर	: प्रशांत पारीक
क्रिएटिव डिजाइनर	: देवेन्द्र देवांगन
मैग्जीन डिज़ाइनर	: युनिक ग्राफिक्स
मार्केटिंग मैनेजर	: किरण नायक
एडमिनिस्ट्रेशन	: निरूपमा मिश्रा
अकाउंट असिस्टेंट	: प्रियंका सिंह
ऑफिस कॉर्डिनेटर	: योगेन्द्र बिसेन

प्रधान कार्यालय

965/1 कक्कड़ चौक, श्याम नगर रोड,
कटोरा तालाब,रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन : 0771-4044047
ईल : khabar@aamaadmi.in

कार्यालय

प्लाट नं.118, कंचन बाग, राजनांदगांव

प्रकाशक

उमेश कुमार बंसी, क्वाटर नंबर 10, एम.एम. रियल स्टेट कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं मुद्रित

विशेष- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गए विचार, लेखकों के अपने है। इसमें संपादक / मुद्रक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संपादक / मुद्रक जिम्मेदार नहीं होगा। इस पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद के लिए सुनवाई क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

अनुक्रमणिका

जनवरी 2022

इस अंक में

कालीन बुनाई से महिलाएं जीवन में भर रहीं सुनहरे रंग

आदिवासी महिलाएं कालीन बुनाई से अपने जीवन में रंग भर रहीं हैं। आत्मविश्वास से लबरेज इन महिलाओं का कहना है कि उन्हें इस नए हुनर से उनमें नया आत्मविश्वास जगा है... 5

गन्ने की खेती से 5 लाख की कमाई 8

गन्ने की खेती किसानों के लिए फायदेमंद होती है...

ज्वार-बाजरे को सुपरफूड क्यों ... 10

मेरे बचपन के दिनों में मैं अक्सर अपने दादा-दादी के घर

शराब तस्कर पर करें कार्यवाही : लखमा 19

मंत्री कवासी लखमा ने आबकारी अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली...

अंडे के कारोबार से 8 लाख की कमाई 20

समूह की महिलाओं ने 3 महीने में 8 लाख से अधिक के बेचे अंडे

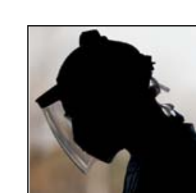

ओमिक्रॉन से खतरनाक वैरिएंट की आशंका 24

ओमिक्रॉन वैरिएंट का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है ...

अब भूमिहीन किसानों की बारी... 28

हितग्राहियों को गणतंत्र दिवस पर पहली किश्त ...

लापरवाही से फिर
आफत की घड़ी आई

उमेश के बंसी
(प्रबंध संपादक)

छ हम सबने पिछले साल को देखा, शायद ऐसी त्रासदी नहीं देखी थी, अपनों को खोया और खूब रोया। फिर सम्भले और जिंदगी की रफ्तार को आगे करने के लिए दौड़ने लगे। फिर क्या पता था कि लापरवाही के ऐसी होगी कि हम फिर घर अंदर रहने को मजबूर हो जाएंगे। पर इस दौर में थोड़ा परेशानी फिर शायद आने वाली है। रिसचर्स भी बड़ी आफत की चेतवानी दे रहे है। सबसे बड़ी वजह है कि हम मानने को तैयार नहीं होते है। इधर प्रशासन भी लगाम कसने में नाकाम है, यही वजह है कि हम अब थोड़ा कोरोना के पिक दौर में आ चुके है। नया साल जोश और उत्साह के साथ मनाया, पर चेतावनी पहले से थी कि लापरवाही हुई तो फिर से हम पिछले दो साल से जो झेलते आ रहे है, उसी दौर में चले जाएंगे। अब कोरोना इतनी तेजी से बढ़े है कि सरकार व जिला प्रशासन ने उम्मीद नहीं की थी। जिला प्रशासन को मालूम था कि 29 दिसंबर से मामले 100 से ऊपर चले गए हैं। यहां जिला प्रशासन ने लापरवाही की। नववर्ष के आयोजनों पर रोक नहीं लगाई। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। इसी का परिणाम है कि कोरोना के मामले 30दिसंबर को 150,31 दिसंबर को 190 मामले आए। 1 जनवरी को 279,2 जनवरी को 290 व 3 जनवरी को 698 मामले आए। जिस तरह तीन दिन में कोरोना के मामले कई गुना बढे पर मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाकर कलेक्टरों को कोरोना के मामले रोकने के लिए जो भी जरूरी है वह सब कदम उठाने को कहा है। सीएम भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट किया है सरकार कोरोना नियंत्रण के लिए गैर कमर्शियल गतिविधियों पर सीमित या पूरी तरह रोक लगाने की पक्षधर है। यह अच्छी बात है। इससे कमर्शियल गतिविधियों पर रोक नहीं लगेगी। इसका फायदा यह होगा कि पिछली बार की तरह अर्थव्यवस्था पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। पिछली बार के लाकडाउन का देश व राज्य की अर्थव्यवस्था पर जो बुरा असर पड़ा था, उससे अब अर्थव्ववस्था उबर रही है। ऐसे में यदि लाकडाउन लगा दिया जाए तो इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा. सरकार ने कलेक्टरो से कहा है कि कोरोना के जहां ज्यादा मामले हैं नाइट कर्फ्यू,धारा 144 सहित जो भी सख्त कदम उठाने पड़े,उठा सकते हैं। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना को रोकने के लिए किस जिले मे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मामला राजधानी रायपुर में मिल रहे है इसलिए यहां कोरोना को रोकने के लिए सख्त कदम उठान की सबसे ज्यादा जरूरत है। कोरोना को रोकने के लिए जरूरी है कि जिला प्रशासन भी सजग रहे और आम लोग भी सजग रहे, कोरोना से बचाव के नियमों का खुद पालन करें तथा दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करें।

हस्तशिल्प विकास बोर्ड की 6 बुनाई केन्द्रों में 114 महिलाओं को कालीन बुनाई से मिल रहा रोजगार

कालीन बुनाई से महिलाएं
जीवन में भर रहीं सुनहरे रंग

हस्तशिल्प विकास बोर्ड की योजना के तहत सरगुजा जिले की 114 महिलाओं को कालीन बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 114 महिलाओं को कालीन निर्माण से जोड़ा गया। इनमें रघुनाथपुर की 20, बटवाही की 20, गंगापुर की 20, सिरकोतंगा की 20, दरिमा की 16 तथा कमलेश्वरपुर की 18 महिलाएं शामिल हैं। तीन माह के प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण केन्द्र में ही कच्चा माल देकर उनसे कालीन तैयार करवाया जा रहा है। इसके अलावा प्रशिक्षण अवधि में उन्हें 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता भी दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बिहान योजना से भी जोड़ा जा रहा है। बिहान समूह की महिलाओं को बुनाई मशीन से लेकर कच्चा माल उपलब्ध कराने में भी सहायता दी जाती है। रघुनाथपुर कालीन बुनाई सेंटर में काम करने वाली श्रीमती सुनीता बघेल ने बताया कि कालीन बुनाई कार्य प्रारंभ करने के लिए बिहान कार्यक्रम से जुड़कर मशीन खरीदने लोन लिया है। बुनाई में प्रयुक्त कच्चे माल और अन्य मटेरियल उन्हें हस्तशिल्प बोर्ड के द्वारा ही उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मशीन में 2 महिलाएं मिलकर कालीन बुनाई का कार्य करती हैं। एक कालीन बनाने में उन्हें लगभग सप्ताह भर का समय लग जाता है। कालीन के साइज के अनुसार महिलाओं को हस्तशिल्प बोर्ड से उनका मेहनताना तत्काल मिल जाता है। इसमे औसतन लगभग 7 से 8 हजार रुपये प्रति माह की कमाई हो जाती है। तैयार हुए कालीन की बिक्री हस्तशिल्प बोर्ड अपने विक्रय केंद्र के माध्यम से की जाती है। श्रीमती बघेल ने बताया कि वर्तमान में सरगुजा का विक्रय केंद्र अम्बिकापुर में स्थित है। सबसे अच्छी बात ये है कि महिलाएं अपने घर के काम निपटाने के पश्चात कालीन बुनाई का कार्य करती हैं। गृह कार्य के साथ-साथ उन्हें आजीविका के लिए कालीन बुनाई का कार्य भी कर रही हैं। इस तरह उन्हें घर के पास ही स्व-रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है और वे सभी महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही हैं।

> “आदिवासी महिलाएं कालीन बुनाई से अपने जीवन में रंग भर रहीं हैं। आत्मविश्वास से लबरेज इन महिलाओं का कहना है कि उन्हें इस नए हुनर से उनमें नया आत्मविश्वास जगा है। उनके परिवार की आमदनी में इजाफा हुआ है।”

नवा छत्तीसगढ़

कोरोना से प्रभावित सड़कों सहित पुलों के कार्यों को मिलेगी गति

नए साल में नया काम

कम होगी दूरियां

> सड़कें वह नहीं जो किसी मुसाफिर को सिर्फ मंजिल तक पहुचायें। सड़कें तो विकास का वह माध्यम भी है, जो मंजिल पर पहुचने वाले मुसाफिरों को विकास से जोड़कर उनकी समस्याएं दूर कर दें।

आवागमन का जरिया और मुसाफिरों को मंजिल पर पहुचाने से लेकर उन्हें विकास की सीढ़ी चढ़ाने और विश्वास कायम करने वाली सड़कें यदि खराब हो तो सफर बोझिल और पीड़ादायक बन जाता है, साथ ही मंजिल तक सही सलामत और समय पर पहुचने का अविश्वास भी मन में उत्पन्न हो जाता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव की तरह सड़कों का उतार चढ़ाव हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देती हैं, और मुकाम को पाने साहस। सड़कविहीन मार्ग अविश्वास को जन्म देता है, वहीं सड़क वाले मार्ग, उसमें चलने वालों के भीतर विश्वास का भाव जगा देते हैं। सकारात्मक माहौल बना देते हैं। ठीक इसी दिशा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लोक निर्माण विभाग लम्बी और छोटी दूरियों के सफर को सहज और सुगम बनाने वाली सड़कों के विकास में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। वह चाहे नक्सलियों से प्रभावित जिला हो या प्रदेश का कोई दूरस्थ अन्य जिला, गाँव हो या शहर। जहाँ जैसी जरूरत है, सड़कों के लिए सरकार के खजाने पूरी तरह से खुले हुए हैं। कोरोना की वजह से प्रभावित हुए साल 2020-21 के बाद नये साल 2022 में प्रदेश की अनेक अपूर्ण सड़कों के साथ नये सड़क और पुल-पुलियों के कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन कार्यों की पूर्णता से छत्तीसगढ़ में आवागमन बेहतर होने के साथ समय की बचत और विकास के द्वार भी खुल जायेंगे। छत्तीसगढ़ के विकास में सहभागी लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए कार्ययोजना तैयार कर काम किया जा रहा है। राज्य मद से विगत 3 साल में लगभग 5974 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया गया है। सितम्बर 2021 तक 3790 कार्यों के लिये 7161 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ सड़क अधोसंरचना विकास निगम अंतर्गत भी प्रदेश के नक्सल प्रभावित सहित अन्य इलाकों में सड़क पुल-पुलिया निर्माण के 504 कार्यों के लिए 5543 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

नक्सल प्रभावित सहित अन्य जिलों में बिछेगा सड़कों का जाल

सड़कें सिर्फ सबका बोझ ही नहीं ढोती है। वह फासलों को दूर कर विकास से भी जोड़ती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़कों के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई है वह प्रदेश के लोगों को विकास से जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित होगी। कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुए निर्माण कार्यों को साल 2022 में गति मिलेंगी। इसमें अनेक योजनाओं की सड़के शामिल है।प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत स्वीकृत 4079 मार्गों में से 472 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। राज्य में इस योजना के 1577 कार्य प्रगति पर और 2030 कार्य निविदा स्तर पर है। इस योजना का उद्देश्य समस्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों को बारहमासी पहुंच मार्ग से जोड़कर लोक कल्याण एवं जनसुविधा के लिए सुगम बनाया जाना है। छत्तीसगढ़ सड़क अधोसंरचना विकास अंतर्गत प्रदेश की महत्वपूर्ण सड़कों एवं पुलों के निर्माण एवं उन्नयन की योजना भी तैयार की गई है। इसके अंतर्गत 504 कार्यों हेतु 5543 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य में एल. डब्ल्यू.ई. (आर.आर.पी.-1) योजना अंतर्गत 51 सड़कें जिसकी लंबाई 1992 किलोमीटर एवं 03 सेतु निर्माण के लिए 3170.95 करोड़ रुपये स्वीकृत है। इस योजना से अब तक 35 सड़क, 03 सेतु के कार्य पूरे किए जा चुके हैं और 16 कार्य प्रगति पर है। आरसीपीएलडब्ल्यू (आर.आर.पी.-2) अंतर्गत अभी तक दो चरणों में 291 सड़क (2478 कि.मी.) एवं 25 पुल हेतु कुल 1637.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। जिसमें से 64 सड़क एवं 06 पुल निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया हैं। आरसीपीएलडब्ल्यू योजना (आर.आर.पी.-2) फेस-3 में 120 कार्य (104 सड़क, 16 पुल) की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है। सी.आर.एफ.योजना अंतर्गत कुल 96 कार्य (77 सड़क, 19 पुल) लंबाई 1825 कि.मी. एवं लागत 2214.20 करोड़ रुपये स्वीकृत है। जिसमें से अब तक 70 सड़क, 12 पुलों का काम पूरा किया जा चुका है और 6 सड़क, 7 पुलों का कार्य प्रगति में है। एशियन डेव्लपमेंट बैंक की सहायता कार्य के अंतर्गत कुल 24 मार्ग हेतु 3369.77 करोड रुपए.की स्वीकृति प्राप्त है। राज्य में स्वीकृत सभी 24 कार्य प्रगति पर है।

इसी तरह प्रदेश में सेतु निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने की प्राथमिकता है। अभी तक 131 वृहद पुल पूर्ण और 141 वृहद पुलों के कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 2018 से सितंबर 2021 तक 06 रेल्वे ओव्हर ब्रिज भिलाई नेहरू नगर, शंकर नगर रायपुर, लालखदान बिलासपुर, गोंदवारा रायपुर एवं बिलासपुर कटनी रेलमार्ग गौरेला एवं खमतराई में पुराने आर.ओ.बी. का चौड़ीकरण कार्य तथा 05 रेल्वे अंडर ब्रिज भिलाई नेहरू नगर, बिलासपुर के चुचुहियापारा, भिलाई पावर हाऊस, दुर्ग दल्लीराजहरा एवं डोंगरगढ़ का कार्य पूर्ण किया गया है। जवाहर सेतु योजना अंतर्गत पुलों का निर्माण कर पहुंचविहीन गांवों तक आवागमन हेतु कनेक्टीविटी की योजना है। इसके लिए बजट वर्ष 2019-20 में 100 पुल एवं वर्ष 2020-21 में 94 पुल कार्य शामिल हैं। वर्तमान में 667 करोड़ रुपये और 90 पुल कार्य की स्वीकृति दी गई है। जिसमें से 4 कार्य पूर्ण, 58 प्रगति पर तथा 37 कार्य निविदा स्तर पर है।

गन्ने की खेती से 5 लाख की कमाई

गन्ने की खेती किसानों के लिए फायदेमंद होती है। जब वे इसमें वैल्यू एडिशन मॉडल पर फोकस करते हैं तो कमाई और अधिक हो जाती है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के रहने वाले प्रवीण पधारिया ने ऐसी ही एक पहल की है। पहले वे पारंपरिक खेती करते थे, जिसमें लागत के मुकाबले कमाई ज्यादा नहीं हो पाती थी। अब वे गन्ने की खेती कर रहे हैं और इससे बने प्रोडक्ट की गुजरात और दूसरे राज्यों में मार्केटिंग कर रहे हैं। इससे सालाना 4-5 लाख रुपए वे मुनाफा कमा रहे हैं।

कपास और ट्रैडीशनल खेती में नहीं हो रहा था मुनाफा

प्रवीण कहते हैं कि सुरेंद्रनगर जिले में पानी की कमी रहती है। इसलिए यहां कपास, जीरा, गेहूं, चना, बाजरा जैसी पारंपरिक फसलों की खेती की जाती थी। हरियाली का तो दूर-दूर तक कोई निशान नहीं दिखता था। कई बार तो कपास की फसलें बीमारी का भी शिकार हो जाती थीं। लिहाजा हमारी कमाई नहीं हो पाती थी। इसलिए हम किसी नई फसल के बारे में प्लान कर रहे थे।

इसके बाद प्रवीण के एक परिचित ने गन्ने की खेती का सुझाव दिया। तब उनके गांव में नर्मदा नहर का पानी भी आने लगा था। यानी अब सिंचाई की भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। फिर क्या था उन्होंने 7 बीघे जमीन में गन्ने की खेती शुरू कर दी। उम्मीद के मुताबिक उन्हें रिजल्ट भी मिला और अच्छी पैदावार हुई। इसके बाद उन्होंने लोकल मार्केट में गन्ना और उससे गुड़ बनाकर बेचना शुरू किया। इससे उन्हें पहले के मुकाबले अच्छी आमदनी हुई।

वैल्यू एडिशन खेती पर फोकस, आमदनी बढ़ी

प्रवीण कहते हैं कि जब हम लोग कपास की खेती करते थे तो साल के 50 हजार रुपए भी नहीं बचते थे, लेकिन जब से हमने गन्ने की खेती करनी शुरू की है हर साल 4-5 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है। चूंकि हम लोग पूरी तरह नेचुरल फार्मिंग करते हैं, बाहर से कोई खाद या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए लागत भी कम आती है। मेरे पास कुछ गायें हैं, उनके गोबर को ही खाद के रूप में इस्तेमाल करता हूं। इससे प्रोडक्शन भी बढ़िया होता है और जमीन को नुकसान भी नहीं होता।

इसके अलावा अब हम लोग वैल्यू एडिशन मॉडल पर फोकस कर रहे हैं। गन्ने से हम गुड़ और अलग-अलग फ्लेवर की कैंडी बनाकर गुजरात और दूसरे राज्यों में भेजते हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोगों से भी हमारा करार है जो खेत से गन्ना ले जाते हैं और उससे जूस निकालकर बेचते हैं। फिर मुझे पैसे दे जाते हैं। इस तरह हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती है।

अब कई किसान गन्ने की ओर रुख कर रहे हैं

प्रवीण कहते हैं कि जब मैंने गन्ने की खेती की तो कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। उनका कहना था कि मैं अपने खेत को बर्बाद कर रहा हूं। हालांकि, मुझे पता था कि जो कर रहा हूं उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा और अगर नहीं भी मिलेगा तो कम से कम अभी जो कर रहा हूं, उससे तो बेहतर ही होगा। खैर पहले साल मेरी मेहनत रंग लाई और अच्छा प्रोडक्शन हुआ। इसके बाद गांव के कई लोगों ने गन्ने की खेती शुरू कर दी। वे कहते हैं कि आज मेरे गांव में तो लोग गन्ने की खेती करते ही हैं साथ ही दूसरे गांव के लोग भी इसकी तरफ रुख कर रहे हैं। जिसमें सुरेंद्रनगर जिले के खोलडियाड, टेम्बा, रामपारा और बाला गांव के लोग शामिल हैं। यहां के किसानों ने 100 बीघे से ज्यादा जमीन में गन्ना लगाया है।

गन्ने से कैसे तैयार करते हैं गुड़

प्रवीण बताते हैं कि गन्ने की प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता है। 10 हजार रुपए से भी कम में इसका सेटअप तैयार किया जा सकता है। एक बार जब फसल तैयार हो जाए तो उसे खेत से काट लेते हैं। इसके बाद गन्ने को अच्छी तरह से साफ किया जाता है ताकि कहीं कोई गंदगी नहीं रहे। फिर मशीन की मदद से गन्ने का रस निकाला जाता है। इस रस को पहले कड़ाही में गर्म किया जाता है।

जब यह खौलने लगता है तो इसे दूसरी कड़ाही में डाल दिया जाता है। इसके कुछ देर बाद इसे तीसरी कड़ाही में शिफ्ट किया जाता है। ये सबसे अहम स्टेप होता है। इसमें हम गुड़ को अच्छी तरह से प्योरीफाई करते हैं और खुशबू के लिए अलग-अलग फ्लेवर यूज करते हैं। कुछ देर बाद ये गुड़ मार्केटिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। जिसे हम मनचाहे आकार में काट कर पैक कर सकते हैं।

बागपत से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव है ढिकाना। गांव में घुसते ही आपको गुड़ की सौंधी खुशबू का एहसास होगा। ये गुड़ पूरी तरह ऑर्गेनिक और सेहत के लिए फायदेमंद है। दो साल पहले इसी गांव के मनोज आर्य ने ऑर्गेनिक गुड़ बनाना शुरू किया था। अब वे रोल मॉडल बन गए हैं। गांव के ज्यादातर किसान उनसे ट्रेनिंग लेकर ऑर्गेनिक गुड़ तैयार कर रहे हैं और अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। मनोज हर साल 5-6 लाख रुपए गुड़ बेचकर कमा लेते हैं।

चंडीगढ़ में रहने वाले भूपेश सैनी देशभर के गन्ना किसानों से उनकी उपज और प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर उसका वैल्यू एडिशन करके मार्केटिंग करते हैं। इससे उनकी कमाई तो होती ही है, साथ ही किसानों को भी उनकी उपज की अच्छी कीमत मिलती है। उनके साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से हजारों किसान जुड़े हैं। फिलहाल इससे वे हर महीने 40 लाख रुपए का टर्नओवर हासिल कर रहे हैं।

ज्वार-बाजरे को सुपरफूड क्यों कहा जा रहा

> मेरे बचपन के दिनों में मैं अक्सर अपने दादा-दादी के घर उत्तर प्रदेश जाया करती थी. मैं देखती थी कि मेरी दादी सादी ज्वार-बाजरे की रोटी खी रही है. वो आटे में धीरे-धीरे पानी डालकर उसे गूथतीं और आटा तैयार कर लेने के बाद वो उसे छोटे-छोटे टुकड़े बना लेतीं. इसके बाद वो उन आटे की लोइयों को दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में रखकर धीरे-धीरे थापतीं.

चकला-बेलन के बिना वो दोनों हाथों की हथेलियों के बीच थाप-थाप कर गोल रोटियां तैयार कर लेतीं और फिर उसे मिट्टी के चूल्हे पर, लकड़ी की आंच पर सेंकती. जब वो मुझे रोटियां परोसती थीं, मैं अपनी नाक चढ़ा लेती थी. मुझे कभी समझ नहीं आता था कि आखिर वो पतली, अधिक मुलायम और खाने में नरम रोटियों की जगह ज्वार-बाजरे जैसे मोटे अनाज की रोटी को इतनी तवज्जो क्यों देती हैं. लेकिन कुछ सालों पहले, मैंने भी वही सबकुछ खाना शुरू कर दिया जो मेरी दादी मां खाया करती थीं. मैंने अपने किचन से गेंहू का आटा हटाकर उसकी जगह बाजरे का आटा लाकर रख दिया. हालांकि अब रोटी खाने में मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं इसे छोड़ नहीं पायी क्योंकि कुछ दिनों तक ये रोटी खाने के बाद मुझे खुद लगा कि यह ज्यादा सेहतमंद है.

बढ़ रहा है मोटे अनाज का चलन

आटे की बजाय मोटे अनाज की रोटियां खाने वाली मैं अकेली नहीं. खेती-किसानी के जानकार बीते कुछ सालों से यह करते आए हैं. बीते कुछ सालों में कई ऐसी फसलें खेतों में और ऐसा खाना प्लेटों में लौट आया है जिन्हें कुछ वक्त पहले तक बिल्कुल भुला दिया गया था. इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स की डायरेक्टर जनरल डॉ. जैकलीन हॉग्स कहती हैं, ह्लमोटे अनाज को खेत में और प्लेट में वापस लाने के लिए और इस पर लगे ह्यभूली हुई फसलह्ल के टैग को हटाने के लिए ठोस वैश्विक प्रयास की जरूरत है.ह्व साल 2018 को भारत में ह्यईयर ऑफ मिलेट्सह्ल के रूप में मनाया गया. इसके अलावा भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को ह्यइंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्सह्ल के रूप में मनाने का फैसला किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल लोगों को मोटे अनाज से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में जागरुक किया जाएगा. साथ ही खेती के लिए उनकी उपयोगिता के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा. मोटे अनाज खराब मिट्टी में भी उपज सकते हैं और उन्हें तुलनात्मक रूप से कीटनाशक की भी उतनी जरूरत नहीं होती है.

हर तरह से अच्छे मोटे अनाज

डॉ. हॉग्स के मुताबिक, ह्लमोटे अनाज तेजी से चलन में लौट रहे हैं. इन्हें स्मार्ट फूड के तौर पर पहचाना जा रहा है क्योंकि वे धरती के लिए, किसानों के लिए और आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं.ह्व वो कहती हैं, ह्लइन्हें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है और ये अधिक तापमान में आसानी से बढ़ते हैं. ये फसल किसानों के लिए अच्छी है क्योंकि इनकी पैदावार दूसरी फसलों की तुलना में आसान है और साथ ही ये कीट-पतंगों से होने वाले रोगों से भी बचे रहते हैं. मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं क्योंकि इनमें पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं. अध्ययनों के मुताबिक, बाजरे से मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल में सुधार होता है. ये कैल्शियम, जिंक और आयरन की कमी को दूर करता है. और सबसे जरूरी बात यह कि यह ग्लूटेन-फ्री होता है.ह्व

इस बात में अचरज नहीं है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ मोटे अनाजों को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं. भारत में करीब 8 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं. हर साल करीब 1.7 करोड़ लोग हृदय रोग के कारण दम तोड़ देते हैं और देश में 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिनमें आधे से अधिक गंभीर रूप से कुपोषित हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में देश से कुपोषण को खत्म करने के लिए ह्यमिलेट रवोल्यूशनह्ल की बात कही थी. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए यह असंभव काम नहीं होगा क्योंकि सालों से मोटा अनाज भारतीयों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत रहा है.

सदियों से रहा है भोजन का मुख्य स्रोत

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के निदेशक विलास टोनपी के मुताबिक, मानव जाति को पुराने वक्त से जिन खाद्यान्नों के बारे में जानकारी रही है वो जौ और बाजरा जैसे मोटे अनाज हैं. वह कहते हैं, ह्लसिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी बाजरे आदि की पैदावार होती थी. 21 राज्यों में इसकी खेती की जाती है और हर राज्य और क्षेत्र के अपने कि स्म के अनाज हैं जो ना सिर्फ.उनकी खाद्य संस्कृति का हिस्सा हैं बल्कि उनके धार्मिक अनुष्ठानों का भी हिस्सा हैं.ह्व भारत प्रतिवर्ष करीब 1.4 करोड़ टन बाजरे की पैदावार करता है. इतना ही नहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश भी है. विलास टोनपी के मुताबिक, ह्ललेकिन बीते 50 सालों में कृषि योग्य भूमि घटकर 3.8 करोड़ हेक्टेयर से 1.3 करोड़ हेक्टेयर ही रह गयी है और इसी के साथ 1960 के दशक में होने वाले बाजरे की पैदावार घटकर के मुकाबले आज पैदावार 6 फीसद पर आ गयी है.ह्व डॉक्टर टोनपी के अनुसार देश में बाजरे की पैदावार में गिरावट 1969-70 के समय में शुरू हुई थी. विलास टोनपी बताते हैं, ह्लउस समय तक भारत खाद्य सहायता प्राप्त कर रहा था और अपनी एक बड़ी आबादी के पोषण के लिए अनाज का आयात करता था. खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए और कुपोषण पर काबू पाने के लिए भारत में हरित क्रांति हुई और उसके परिणामस्वरूप चावल और गेंहूं की अधिक पैदावार वाली किस्मों को उगाया जाना शुरू किया गया.ह्व

भारत में 1960 और 2015 के बीच, गेंहू का उत्पादन तीन गुना से भी अधिक हो गया और चावल के उत्पादन में 800 फीसद की वृद्धि हुई. लेकिन इस दौरान बाजरा जैसे मोटे अनाजों का उत्पादन कम ही बना रहा. डॉ. हॉग्स कहती है, ह्लबीते सालों में चावल और गेहूं की उपज बढ़ाने पर बहुत अधिक जोर दिया गया और इस दौरान बाजरा और कई दूसरे पारंपरिक खाद्य की उपेक्षा हुई और जिसकी वजह से उनका उत्पादन प्रभावित हुआ.ह्व वह कहती हैं, ह्लइन्हें पकाना इतना आसान नहीं है और आज के समय में किसी के पास इतना वक़्त भी नहीं है. दशकों से इनका बेहद कम इस्तेमाल किया जा रहा है. बाजार ने भी इनकी उपेक्षा ही की है. लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि आपकी प्लेट में अलग-अलग स्वाद और अलग-अलग तरह के पोषक तत्वों होना बहुत जरूरी है.ह्व वह कहती हैं, ह्लऐसा करने के लिए जिन फसलों को भुला दिया गया उन पर भी चावल-गेंहूं और दूसरी व्यवसायिक फसलों की तरह ही ध्यान देना होगा.ह्व हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं ज्वार-बाजरा अब धीरे-धीरे चलन में लौट रहे हैं.

बाजरे की मांग बढ़ाने की कोशिशें

कृषि वैज्ञानिकों इन मोटे अनाज को दोबारा से चलन में लाने के लिए कई तरह के उपाय सुझाए थे और उनकी सुझाए रणनीति के परिणाम भी अब दिखने भी लगे हैं. डॉ. टोनपी के अनुसार, पिछले दो सालों में बाजरे की मांग में 146 फीसद की वृद्धि दर्ज की गयी है. मोटे अनाज जैसे बाजरा आदि से बने कुकीज, चिप्स, पफ और दूसरी चीजें सुपरमार्केट और ऑनलाइन स्टोर्स में बेचे जा रहे हैं. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लाखों लोगों को एक रुपये प्रति किलो की दर से बाजरा और मोटा अनाज दिया जा रहा है. कुछ राज्यों में दोपहर के खाने में में भी इन मोटे अनाजों से बने व्यंजन परोसे जा रहे हैं. मोटे अनाज के लिए लोगों में बढ़ा दिलचस्पी तेलंगाना राज्य के आदिवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. पी आइला, असिफाबाद की 10 महिलाओं के उस समूह में से एक हैं जिन्हें इक्रीसैट ने रूरल-डे केयर सेंटर में बच्चों को दिए जाने वाला भोजन बनाने की ट्रेनिंग दी है. अपने गांव से फोन पर मुझसे बात करते हुए उन्होंने बताया कि वह खाना बनाने में लगने वाली हर जरूरी चीज की लिस्ट बनाती है और मसालों के बारे में लिखती हैं. वह बताती हैं कि अगस्त में उन्होंने मोटे अनाज से बना 12 टन मीठा और नमकीन व्यंजन बेचा है. आइला कहती हैं कि उन्हें यह नहीं पता कि लोगों का चाव मोटे अनाज के प्रति क्यों बढ़ रहा है लेकिन वह इस बात से खुश हैं कि जिस अनाज को वह जीवन भर अपने मुख्य आहार के रूप में लेती रहीं उसे अब और लोग भी पसंद कर रहे हैं.

“ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमीन से जुड़े हुए किसान होने के साथ ही आम जनता के लिए अत्यधिक संवेदन शील भी हैं। वे जानते हैं छत्तीसगढ़ का व्यक्ति स्वाभिमानी है, अपनी जड़ों से जुड़ा रहना जानता है और चाहता भी है । इसीलिए वे हमेशा छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विरासत को सहेजने ,संवारने में जुटे रहते हैं ।उनका यह सपना है कि हमारे गांव आत्मनिर्भर बने। वे महात्मा गांधी की परिकल्पना के अनुसार सुराजी गांव बनाना चाहते हैं। ”

चार चिन्हारी छत्तीसगढ़ के लिए गेम चेंजर

इसीलिए 17 दिसंबर 2018 को शपथ लेने के बाद ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के चार चिनारी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी का मूल मंत्र दिया, जिसे शुरू में प्रशासनिक अधिकारियों को समझने में दिक्कत हुई लेकिन छत्तीसगढ़िया को ये शब्द अपने गांव, घर के लगे और वे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के गांव वालों की मुश्किलों को समझने और उसका हल करने वाले लगे।

नरवा, गरवा योजना से गांव के गौठान न केवल आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बने बल्कि महिला सशक्तिकरण के भी केंद्र बने क्योंकि वहां किए जाने वाले कामों में गोबर संग्रहण के अलावा वर्मी कल्चर ,बतख पालन, मशरूम पालन भी सब्जी -भाजी उगाने मे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। कोरोना काल में जब गांव में लॉकडाउन के समय पुरुषों को बाहर का काम नहीं मिल रहा था तब इन महिलाओं ने अपनी बारी में सब्जियां उगा कर बेची और परिवार के लिए सहारा बनी। इसी प्रकार स्व सहायता समूहो के माध्यम से अनेक महिलाओं को अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने का मौका मिला और इन सब से उनकी सामाजिक स्थिति भी मजबूत हुई।

नरवा गरवा वाली वाली योजना ने न केवल गांव वालों को आर्थिक रूप से सक्षम किया बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी यह योजना एक गेम चेंजर साबित होगी। इससे ना केवल नालों का संरक्षण हो रहा है बल्कि भूजल स्तर भी बढ़ रहा है और गुरुवा में ऑर्गेनिक खाद वर्मी कंपोस्ट बनने से खेती के लिए भी यह फायदेमंद हो रहा है। यहां तक की इस योजना की चर्चा और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी हो रही है यह शोध का विषय भी बन रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य को एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो छत्तीसगढ़िया संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करते हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ में पोला, छेरछेरा ,तीजा आदि मनाने के लिए अवकाश भी दिया। यह सांकेतिक ही नहीं था बल्कि इसके गूढ अर्थ भी हैं कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना कितना जरूरी है। मुख्यमंत्री केवल किसानों की नहीं बल्कि आदिवासी अंचलों में रहने वाले लोगों की उतनी ही परवाह करते हैं । उनके लिए 31 से अधिक लघु वनोपजो को समर्थन मूल्य में खरीदने का फैसला लिया । उनके उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए इकाइयां खोली गई ।उनके लिए बीमा योजना चालू की गई। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, महतारी एक्सप्रेस आदि के जरिए हजारों आदिवासियों को स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है । स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त में यूनिफॉर्म, पुस्तकें, मिड डे मील मिल रहा है। शहर में रहने वाले वंचित वर्गों के लिए भी स्वास्थ्य सुविधा शुरू की गई हमरअस्पताल के तहत उसे सभी सुविधाओं से लैस किया गया।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार यहां के कलाकारों को भी संरक्षण दे रही है और उन्हें सम्मानित भी कर रही है । युवाओं के हुनर को मंच देने के लिए अगले साल जनवरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी आयोजित किया जा रहा है नवंबर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में जिस प्रकार पूरा शासन -प्रशासन आयोजन को सफल बनाने के लिए लगा रहा उससे समझ में आता है कि मुख्यमंत्री आदिवासियों और कला, संस्कृति को कितना महत्व देते हैं। छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता और सभी धर्मों का समान रूप से आदर होता आ रहा है । इसके प्रमाण सिरपुर के बौद्ध विहार जैनों के मंदिर और यहां के 6-7 शताब्दी के हिंदू मंदिरों से मिलते हैं । छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल माना जाता है और कौशल्या माता यहां की बेटी हैं। इस नाते से यहां भांजे को बहुत महत्व दिया जाता है। शबरी ने जूठे बेर भगवान राम को यही खिलाए थे । ऐसी अनेक लोक कथाएं और मान्यताओं में भगवान राम और माता सीता की कहानियां सुनने को मिलती हैं। इन्ही मान्यताओं को मूर्त रूप देने के लिए राम वन गमन पथ को संवारने का, सहेजने का काम भी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है।

आज हम एक ऐसे छत्तीसगढ़ के निर्माण के साक्षी हो रहे हैं जिसमें सभी के लिए काम है सभी की आवाज सुनी जा रही है, सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, बच्चों को पढ़ाई के भरपूरअवसर मिल रहे हैं महिलाओं को सम्मान मिल रहा है।

नवा छत्तीसगढ़

© Imago

सरहद पर तनाव पर व्यापार पहुँचा 100 अरब डॉलर पार

भारत और चीन के रिश्तों में उतार-चढ़ाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है, जो बताती है कि इस क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्ते और गहरे होते जा रहे हैं. इस साल भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के एक विशाल आँकड़े को पार कर गया है लेकिन दोनों ओर इसकी ज्यादा चर्चा नहीं है.

वजह साफ है, पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं. साल 2001 में 1.83 अरब अमेरिकी डॉलर से शुरू हुआ यह द्विपक्षीय व्यापार इस साल के 11 महीनों के अंदर 100 अरब डॉलर का हो गया. यह दोनों देशों के व्यापार के लिए एक बड़ा मौका है क्योंकि दोनों देशों ने अपने व्यापार के लिए रिश्तों को बेहतर किया है.

कितना हुआ व्यापार

चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स (ऋभ्रउ) के पिछले महीनों के आँकड़ों के अनुसार, भारत-चीन का द्विपक्षीय व्यापार 114.263 अरब डॉलर का हो गया है जो कि जनवरी से नवंबर 2021 के बीच 46.4 फीसदी तक बढ़ा है. भारत का चीन को निर्यात 26.358 अरब डॉलर का हो गया है जो हर साल 38.5 फीसदी बढ़ा है और वहीं भारत का चीन से आयात 87.905 अरब डॉलर हो गया है जो 49 फीसदी तक बढ़ा है.एक ओर द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं 11 महीनों के दौरान भारत का व्यापार घाटा भी तेजी से बढ़ा है. व्यापार घाटा का मतलब है कि भारत ने चीन से जितना सामान बेचा है, उससे ज्यादा खरीदा है. व्यापार घाटा भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है जो कि 61.547 अरब हो गया है. यह इस साल 53.49 फीसदी बढ़ा है. व्यापार घाटे पर भारत की चिंता के बावजूद इस रिकॉर्ड को वर्चुअली दर्ज किया गया. हालांकि इस पर कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है क्योंकि पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध जारी है और इसके कारण दोनों देशों के संबंध पहले से अधिक सुस्त हैं.रिकॉर्ड व्यापार पर सवाल और नाजुक रिश्ते रक्षा विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी ने इस व्यापार बढ़ोतरी पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया है. अपने ट्वीट में

चेलानी ने कहा है, ह्चीन के सीमा अतिक्रमण के बीच मोदी सरकार साल 2021 में चीन के साथ व्यापार में 50 फीसदी की बढ़ोतरी को कैसे सही ठहराती है, जिसमें जनवरी और नवंबर के बीच में 61.5 अरब डॉलर का सरप्लस चीन के पक्ष में है जो कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत के लगभग कुल रक्षा खर्च के बराबर है.ह्पिछले साल पाँच मई को भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध शुरू हुआ था जिसके बाद पैंगोंग लेक इलाके में दोनों के बीच हिंसक झड़पें हुईं और दोनों देशों के कई जवान मारे गए. धीरे-धीरे दोनों देशों ने अपने-अपने इलाके में कई हजार जवानों और भारी हथियारों की तैनाती कर दी.

बिना आपसी संबंधों के दोनों पक्षों को साथ लाना बेहद कठिन

दोनों देशों ने हाई लेवल इकोनॉमिक एंड ट्रेड डायलॉग (ल्एळऊ) तंत्र स्थापित करने का फैसला किया था जिसकी अध्यक्षता चीन के उप-प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री करते. यह द्विपक्षीय व्यापार और व्यापार साझेदारियों समेत भारत के व्यापार घाटे के मुद्दों को भी देखता. चीन ने इस तरह का उच्च स्तरीय तंत्र केवल अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने के लिए स्थापित किया हुआ था. इसके साथ ही दोनों नेताओं ने साल 2020 को इंडिया-चाइना कल्चरल पीपल टू पीपल एक्सचेंज का साल घोषित करने का फैसला किया था जिसके तहत दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर आदान-प्रदान के लिए 70 कार्यक्रम आयोजित किए जाते. इनमें एक दूसरे की विधायिका, राजनीतिक दलों, सांस्कृतिक एवं युवा संगठनों और सेनाओं को समझना था. दुर्भाग्य से पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ा और दोनों पहल नाकाम हो गईं. दोनों देशों के संबंधों पर चीन का क्या मानना है, इस विषय पर वांग ने मिस्री के साथ बैठक के दौरान कहा था कि बिना आपसी संबंधों के दोनों पक्षों को साथ लाना बेहद कठिन है यहां तक कि अगर बीच में कोई पहाड़ न भी हो. उन्होंने कहा, ह्चीन और भारत को एक दूसरे का साझेदार और दोस्त बनना चाहिएह्न कि एक दूसरे के लिए कोई खतरा. पर्यवेक्षकों का मानना है कि डोकलाम और लद्दाख गतिरोध भारत-चीन संबंधों को मौलिक रूप से फिर से कायम करने की एक चेतावनी है जिसमें संबंधों को दोबारा एक नए प्रतिमान और रणनीतिक ढांचे से बनाया जाए. वहीं घरेलू स्तर पर चीन में सत्तारुढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (उढउ) की नवंबर में एक हाई प्रोफाइल सभा हुई जिसमें बीते 100 सालों में पार्टी की बड़ी उपलब्धियों को लेकर एक ह्ऐतिहासिक प्रस्तावह्न पास किया गया. इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रिकॉर्ड रूप से तीसरी बार राष्ट्रपति पद देने के लिए भी रास्ता साफ किया गया था. पार्टी के 100 सालों के इतिहास में यह अपनी तरह का तीसरा ह्ऐतिहासिक प्रस्तावह्न था. पहले के प्रस्ताव पार्टी के संस्थापक माओत्से तुंग और उनके उत्तराधिकारी डेंग सियोपिंग के नेतृत्व में जारी हुए थे. उढउ की 19वीं केंद्रीय कमिटी के छठवें पूर्ण सत्र में इस प्रस्ताव की समीक्षा की गई और इसे स्वीकार किया गया.

रिश्तों को ठप सा कर दिया था

कई बार की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने इस साल फरवरी में पैंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिण से और अगस्त में गोगरा एरिया में पीछे हटना शुरू कर दिया था.31 जुलाई के बीच दोनों पक्षों के बीच 12वें राउंड की बातचीत हुई थी. कुछ दिनों के बाद गोगरा में दोनों सेनाओं ने अपनी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली थी. इसको क्षेत्र में शांति और संयम की दोबारा बहाली की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना गया था. पहाड़ी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (छउअ) पर हर पक्ष ने सीमा पर 50 से 60 हजार जवान तैनात किए हुए हैं. इस संघर्ष की स्थिति में सबसे बड़ी उम्मीद की किरण हटउ (परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र) रही जिसके तहत दोनों देश के विदेश मंत्री और शीर्ष सैन्य कमांडर संपर्क में रहे और तनाव को नियंत्रित किया. लद्दाख गतिरोध ने केवल व्यापार को छोड़कर बाकी सभी रिश्तों को ठप सा कर दिया था.

दोनों देशों की राय

इस साल नवंबर में सिंगापुर में एक पैनल डिस्कशन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा था कि भारत और चीन अपने संबंधों में ह्विशेष रूप से खराब हिस्सेह्न से गुजर रहे हैं क्योंकि बीजिंग ने कई कार्रवाइयों से समझौतों का उल्लंघन किया है, जिसका अभी भी उसके पास कोई ह्ठोस जवाबह्न नहीं है. लद्दाख सीमा गतिरोध का स्पष्ट संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा था, ह्हम अपने संबंधों में खासकर एक बुरे भाग से गुजर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी कई कार्रवाइयां की हैं, जिनसे समझौतों का उल्लंघन हुआ है और उनके पास अभी भी उसका ठोस जवाब नहीं है और संकेत देता है कि कुछ सोचने की जरूरत है कि वे हमारे संबंधों को कहाँ लेकर जाते हैं लेकिन ये जवाब उनको देना है.ह्चीन में भारत के पूर्व राजदूत विक्रम मिस्री ने भी इस मुद्दे को उठाया था. 6 दिसंबर को उनके वर्चुअल विदाई कार्यक्रम के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी के आगे मिस्री ने कहा था कि चुनौतियों के कारण भारत-चीन संबंधों की बड़ी संभावनाओं को हार मिली है. लद्दाख गतिरोध का ज़िक्र करते हुए मिस्री ने वांग से कहा था, ह्हमारे संबंधों में संभावनाएं और चुनौतियां शामिल हैं और यहां तक कि पिछले साल कुछ चुनौतियां सामने आईं जिसने रिश्तों में हमारी संभावनाओं को अपने कब्जे में ले लिया था. जनवरी 2019 में मिस्री ने भारत के राजदूत के रूप में पद को संभाला था. यह ज़िम्मेदारी उन्हें तब मिली थी जब कूटनीतिक कोशिशों के जरिए दोनों देश 2017 के डोकलाम गतिरोध से बाहर आए थे. यह गतिरोध साल 2018 में वुहान में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच पहले अनौपचारिक शिखर सम्मेलन और 2019 में चेन्नई में दूसरे शिखर सम्मेलन में एक लंबे-चौड़े विकास के एजेंडे के बाद समाप्त हुआ था. हालांकि फिर पूर्वी लद्दाख का गतिरोध शुरू हो गया. नई दिल्ली लौटने से पहले मिस्री ने मीडिया के साथ की गई अनौपचारिक बातचीत में याद किया था कि कैसे मोदी और जिनपिंग ने चेन्नई सम्मेलन के दौरान दो महत्वपूर्ण पहल को लेकर उम्मीद की थी और उसे लागू करने पर सहमति जताई थी.

बिना रुके बढ़ेंगे हम

सभी वर्गों के सहयोग से कोरोना की तीसरी लहर को देंगे मात

गोधन न्याय योजना के तहत जारी की 5.37 करोड़ की राशि

गौपालकों को हो चुका 119.41 करोड़ रूपए का भुगतान

राज्य में आर्थिक गतिविधियां नहीं होंगी प्रभावित : मुख्यमंत्री

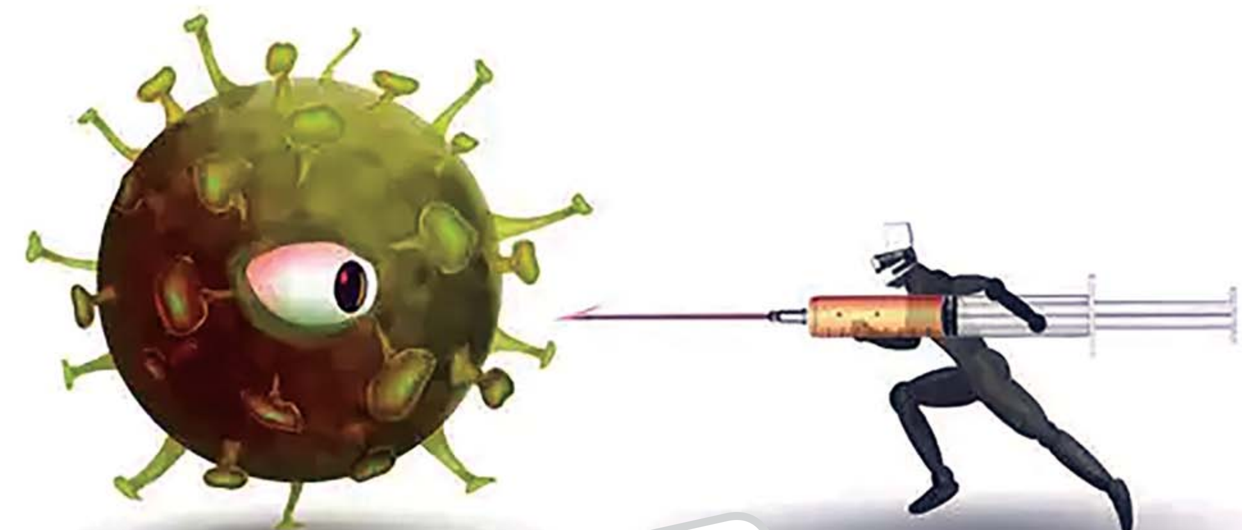

> देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। इस बार कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार ने तीसरी लहर को मात देने के लिए जोरों से तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में आर्थिक गतिविधियां कमजोर न हो, इसके लिए भी खास धान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के सहयोग और सावधानी से हम कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को भी हराएंगे।

उन्होंने लोगों से राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड गाईडलाईन का कड़ाई से पालन करने और सावधानियां बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है, टीकाकरण से छूटे लोगों और 15 से 18 वर्ष के किशोरों से उन्होंने अनिवार्य रूप से टीका लगवाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की बीती दोनों लहरों को छत्तीसगढ़ राज्य ने सभी वर्गों के सहयोग से जिस प्रभावी ढंग निपटने में कामयाबी हासिल की थी, वैसी ही कामयाबी हम तीसरी लहर में भी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद भी हम राज्य की आर्थिक गतिविधियों को पूरी सावधानी के साथ जारी रखेंगे।

गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 37 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें बीते एक पखवाड़े में क्रय गोबर के एवज में 2 करोड़ 78 लाख रूपए भुगतान तथा गौठान समितियों

गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा

गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा है। देश के कई राज्य इसे अपनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान होगा। उन्होंने कहा कि 10591 गौठानों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 7889 गौठान सक्रिय रूप से कामकाज करने लगे हैं। शत-प्रतिशत गौठानों के चालू हो जाने से आय की गतिविधियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट और अन्य उत्पादों के लाभांश से लगभग 100 करोड़ रूपए की आय हो चुकी है। वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट को खेती-किसानी के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों का वर्मी खाद की ओर रूझान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद डीएपी की कमी को पूरा करने में गौठानों में बनी वर्मी कम्पोस्ट ने अहम रोल अदा किया है। उन्होंने गौठानों के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाने वाले मशीने जैसे दोना पत्तल मशीन, धान कुट्टी, कोदो-कुटकी प्रसंस्करण मशीन, हर्बल उत्पाद तैयार करने एवं तेल निकालने वाली मशीन की स्थापना के लिए शासन की योजनांतर्गत अनुदान सहायता दिए जाने का भी प्रावधान करने की बात कही।

कोविड से मृत्यु प्रकरणों के मुआवजा वितरण में तेजी लाएं

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों की बैठक लेकर कोविड-19 संक्रमण से मृत हुए लोगों के परिजनों को राहत राशि वितरण अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को राहत राशि वितरण का कार्य पूरा किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए अपने-अपने जिलों में संक्रमण की रोकथाम के लिए हरसंभव प्रभावी उपाय किए जाने की भी हिदायत दी। संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों को कोविड संक्रमितों के इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कोरोना से बचाव के लिए राज्य में किए जा रहे टीकाकरण की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की प्रथम खुराक ले चुके लोगों को निर्धारित समयावधि में दूसरा खुराक अनिवार्य रूप से लिया जाना है। प्रथम टीकाकरण के दौरान संबंधित लोगों के मोबाईल नम्बर रजिस्टर किए गए है। दूसरे टीकाकरण के लिए निर्धारित समय के भीतर उन्हें मोबाइल के माध्यम से संदेश भेजा जाए। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को लगने वाले कोवेक्सीन टीकाकरण के लिए सभी हाई-हायर सेकेण्डरी स्कूलों में टीकाकरण शिविर अनिवार्य रूप से चलाया जाना है।

को एक करोड़ 70 लाख और महिला समूहों को 89 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल है। गोबर खरीदी के एवज में राज्य के गौपालकों को 119.41 करोड़ रूपए हो चूका हैं। गौठान समितियों को अब तक 44.43 करोड़ रूपए तथा महिला स्व-सहायता समूहों 28.88 करोड़ रूपए राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना को हम मिशन मोड में संचालित कर रहे हैं, ताकि इसके जरिए गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से मार्केट की डिमांड के आधार पर प्रोडक्ट तैयार है और उसकी मार्केटिंग से समूह को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरूआत करने के बाद अब गोबर से प्राकृतिक पेंट के निर्माण की ओर हम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते सवा सालों में गौठान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। गौठानों के जरिए स्वावलंबन के कार्यों में पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों को मार्केट की डिमांड के अनुसार उत्पादन तैयार करने की ट्रेनिंग देने की बात कही।

कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में अब तक 3.15 करोड़ टीके लगाए गए

प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक (3 जनवरी तक) कुल तीन करोड़ 15 लाख 26 हजार 212 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक के 96 प्रतिशत आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका और 63 प्रतिशत को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण की शुरूआत के बाद 3 जनवरी को पहले ही दिन एक लाख 85 हजार 906 किशोरों का टीकाकरण किया गया है। प्रदेश भर में इस आयु वर्ग के लिए लक्षित 11 प्रतिशत से अधिक किशोरों को कोरोना से बचाव का टीका पहले ही दिन लगाया गया। राज्य में 18 वर्ष से अधिक के एक करोड़ 89 लाख 41 हजार 014 लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका और एक करोड़ 23 लाख 99 हजार 292 को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं।

आबकारी मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों की बैठक ली

शराब तस्कर और मिलावटखोरों पर करें कार्यवाही : लखमा

> वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री कवासी लखमा ने राज्य के आबकारी अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। बैठक में लखमा ने अधिकारियों को प्रदेश के देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में मदिरा के निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय को नियंत्रित करने, दूसरे राज्यों से अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में मदिरा तस्करी कर विक्रय करने वालों एवं मदिरा में मिलावट करने वालों के साथ कोचियों पर भी सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

सचिव सह आयुक्त आबकारी निरंजन दास ने बैठक में सभी जिला अधिकारियों को कहा कि वे अवैध मदिरा पर नियंत्रण स्थापित करते हुए स्थानीय स्तर पर कच्ची एवं जहरीली मदिरा का निर्माण एवं विक्रय न हो इसके विरूद्ध कार्यवाही कर अंकुश लगाएं। साथ ही आबकारी राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए मदिरा के विक्रय एवं उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिए जाने हेतु निर्देशित किया।

अन्य प्रान्तों से छत्तीसगढ़ में होने वाली मदिरा तस्करी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए आबकारी जांच चौकियों में कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। आयुक्त दास ने नववर्ष 2022 के आगमन पर होटल-बार-रेस्टोरेंट आदि पर मदिरा के संग्रहण एवं विक्रय पर विशेष ध्यान देते हुए नियंत्रण रखने के लिए संभाग एवं जिला स्तर पर टीम गठित कर निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं।

इस बैठक में विशेष सचिव सह प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड ए.पी. त्रिपाठी, अपर आयुक्त आबकारी राकेश कुमार मण्डावी एवं आर.एस. ठाकुर सहित मुख्यालय और संभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

समूह की महिलाओं ने तीन महीने में 8 लाख से अधिक के बेचे अंडे

अंडे के कारोबार से 8 लाख की कमाई

अंबिकापुर के गोठानों में मुर्गीपालन से समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, वही दूसरी तरफ यहां के अंडों को आंगनबाड़ी केंद्र में आपूर्ति होने पर बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध हो रहा है जिससे कुपोषण मोचन के लिए बड़ा जरिया बन गया है। 7 गोठानों में मुर्गीपालन कर तीन महीने में ही स्व सहायता समूह की महिलाओं ने 8 लाख 40 हजार रुपये के अंडे बेचकर आय अर्जित की है।

कलेक्टर संजीव कुमार झा के मार्गदर्शन में जिले के 7 आदर्श गोठानों में आधुनिक पद्धति से समूह की महिलाओं द्वारा मुर्गीपालन किया जा रहा है। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा महिलाओं को थ्री टियर केज पद्धति से मुर्गीपालन का प्रशिक्षण दिया गया है और प्रत्येक गोठान में 250 नग मुर्गी भी प्रदाय की गई है। अम्बिकापुर जनपद में आदर्श गोठान सोहगा व मेण्ड्रा कला, उदयपुर में सरगवां, लखनपुर में पुहपुटरा, बतौली में मंगारी, मैनपाट में उड़ुमकेला और लुंड्रा में बटवाही गोठान में महिलाओं द्वारा मुर्गीपालन का कार्य किया जा रहा है। अक्टूबर से दिसम्बर तक तीन महीने में एक गोठान में 20 हजार अंडे का उत्पादन हुआ इस हिसाब से 7 गोठानों में तीन महीने में 1 लाख 40 हजार अण्डों का उत्पादन हुआ। प्रति अंडे 6 रुपये के दर से आंगनबाड़ी केंद्रों को बेचा गया जिससे 8 लाख 80 हजार रुपये का आय अर्जित हुई। इस प्रकार प्रत्येक गोठान में हर माह 20 हजार रुपये के अंडे बेचे गए।

पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ सी.के. मिश्रा ने बताया कि मुर्गीपालन के लिए भवन का निर्माण मनरेगा से किया गया है जबकि मुर्गियों के लिए आहार एवं दवा की व्यवस्था डीएमएफ से किया गया है। तकनीकी रूप से मुर्गीपालन हेतु प्रशिक्षण और देख-रेख का कार्य पशुपालन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

देश में सबसे कम बेरोजगारी हमारे राज्य में

सीएमआईई ने जारी किये आंकड़े : छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 2.1 प्रतिशत, जबकि देश में 7.7 प्रतिशत

> सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन द्वारा हाल ही में जारी किये गये बेरोजगारी के आंकड़ों ने एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता का परचम बुलंद कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 2.1 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे क्रम पर आया है।

दिसंबर 2021 की स्थिति के अध्ययन के बाद सीएमआईई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर कर्नाटक में 1.4 प्रतिशत और सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 34.1 प्रतिशत बताई गई है। छत्तीसगढ़ ने समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था, जिसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही। तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही। अब नये आंकड़ों के मुताबिक जहां देश में बेरोजगारी दर में लगातार चिंताजनक उछाल है, वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर केवल 2.1 प्रतिशत है। नये आंकड़ों के मुताबिक गुजरात 1.6 प्रतिशत के साथ कम बेरोजगारी वाला दूसरा राज्य है, जबकि पड़ोसी ओड़िशा 1.6 प्रतिशत के साथ तीसरे क्रम पर एवं मध्यप्रदेश 3.4 प्रतिशत के साथ 07 वें क्रम पर है। उत्तरप्रदेश में 4.9 प्रतिशत की बेराजगारी दर है। असम 5.8 प्रतिशत के साथ 12 वें क्रम पर है। राजस्थान में 27.1 प्रतिशत, झारखंड में 17.3 और बिहार में 16 प्रतिशत बेरोजगारी की दर रही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जनवरी 2021 की स्थिति में देश में बेरोजगारी दर 6.52 फीसदी थी जिसमें शहरी बेरोजगारी 8.9 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 5.81 प्रतिशत थी, वहीं दिसंबर 2021 की स्थिति में देश में बेरोजगारी की दर 7.7 प्रतिशत रही जिसमें शहरी बेरोजगारी 9.1 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 7.1 प्रतिशत रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन 45 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में सतत अध्ययन करके डेटाबेस का निर्माण करता आया है और इसके द्वारा जारी आंकड़ों को प्रामाणिक माना जाता है।

कुपोषण से जीत रहे जंग

> मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में शुरू हुए कुपोषण मुक्ति अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के 2020-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक बच्चों के वजन के आंकड़े देखे जाएं तो कुपोषण की दर 6.4 प्रतिशत कम होकर 31.3 प्रतिशत हो गई है।

यह दर कुपोषण की राष्ट्रीय दर 32.1 प्रतिशत से भी कम है। वर्ष 2015-16 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों में वजन के अनुसार कुपोषण की दर 37.7 प्रतिशत और राष्ट्रीय कुपोषण दर 35.8 प्रतिशत थी। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय कुपोषण की दर में जहां सिर्फ 3.7 प्रतिशत की कमी आई और कुपोषण 32.1 प्रतिशत है, वहीं छत्तीसगढ़ ने 6.4 प्रतिशत कमी लाने में सफलता पाई है। उल्लेखनीय है कि बघेल की पहल पर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया गया। इसके तहत विभिन्न योजनाओं को एकीकृत करने के साथ समन्वित प्रयास किये गए। जिससे परिणामस्वरू प्रदेश के लगभग एक लाख 60 हजार बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। प्रदेश में महिला एवं बाल

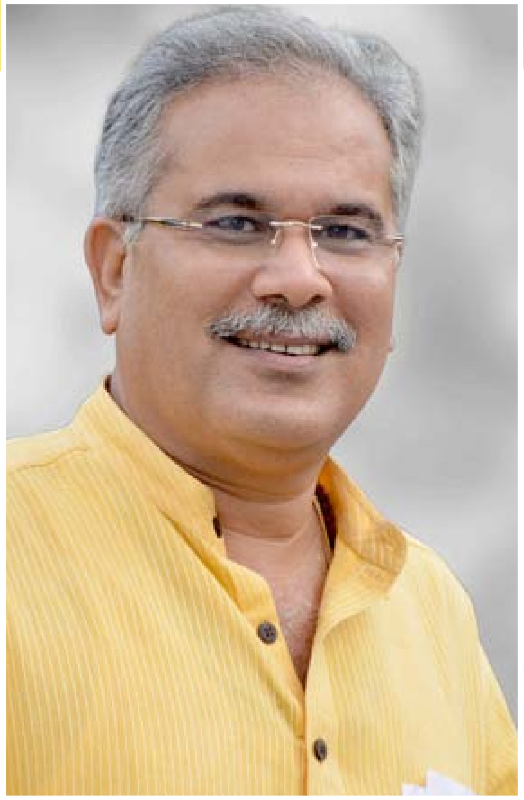

ढाई साल में करीब एक लाख 60 हजार बच्चे हुए कुपोषण मुक्त

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में कुपोषण की दर 6.4 प्रतिशत कम होकर 31.3 प्रतिशत हुई

बघेल की पहल पर शुरू मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के आए सकारात्मक परिणाम

विकास मंत्री अनिला भेंड़िया के निर्देशन में जुलाई 2021 में आयोजित वजन त्यौहार के आंकड़े देखे जाएं तो राज्य में केवल 19.86 प्रतिशत बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। वजन त्यौहार में लगभग 22 लाख बच्चों का वजन लिया जा कर पारदर्शी तरीके से कुपोषण के स्तर का आंकलन किया गया है। डाटा की गुणवत्ता परीक्षण और डाटा प्रमाणीकरण के लिए बाह्य एजेंसी की सेवाएं ली गई थी। छत्तीसगढ़ में जनवरी 2019 में हुए वजन त्यौहार में लगभग 4 लाख 33 हजार 541 कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन किया गया था। इनमें से नवम्बर 2021 की स्थिति में लगभग एक तिहाई 36.86 प्रतिशत अर्थात एक लाख 59 हजार 845 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए है। जो कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही कम समय में ही प्रदेश में कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है, इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व और उनकी दूरदर्शी सोच को जाता है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के प्रदेश में शुरू होने के बाद से लगभग 4 लाख 39 हजार बच्चों और 2 लाख 59 हजार महिलाओं को गरम भोजन और पूरक पौष्टिक आहार से लाभान्वित किया गया है। स्थानीय उपलब्धता के आधार पर महिलाओं और बच्चों को फल, सब्जियों सहित सोया और मूंगफली की चिक्की, पौष्टिक लड्डू, अण्डा सहित मिलेट्स के बिस्कुट और स्वादिष्ठ पौष्टिक आहार दिया गया। इससे बच्चों में खाने के प्रति रूचि जागी और तेजी से कुपोषण की स्थिति में सुधार आया। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सुपोषण को प्राथमिकता क्रम में रखते हुए इसके लिए राज्य में डीएमएफ, सीएसआर और अन्य मदों की राशि का उपयोग किये जाने की अनुमति मुख्यमंत्री बघेल ने दी और जनसहयोग लिया गया। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

टिफिन व्यवस्था के माध्यम से गरम भोजन

मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर विगत वर्ष कोरोना काल में प्रदेश में घर-घर जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने पूरक पोषण आहार और रेडी-टू-ईट वितरण कर महिलाओं और बच्चों के पोषण का ख्याल रखा। वहीं वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 4 प्रतिशत से अधिक कोरोना पॉजिटिविटी दर वाले ऐसे जिले जहां कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए आंगनबाड़ी तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को बंद किया गया है, वहां सभी श्रेणी के पात्र हितग्राहियों को रेडी-टू-ईट वितरण जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गर्भवती माताओं एवं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को घर-घर जाकर टिफिन व्यवस्था के माध्यम से गरम भोजन प्रदान करने कहा है।

ओमिक्रॉन बढ़ने से खतरनाक वैरिएंट की आशंका

कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैलेगा, उतनी ही जल्दी वायरस के नए वैरिएंट के आने की आशंका है। हल्थ की सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर कैथरीन स्मॉलवुड का कहना है कि ओमिक्रॉन की तेज संक्रमण की दर का उल्टा असर पड़ सकता है।

ओमिक्रॉन घातक है, संक्रमण से मौत की आशंका

कैथरीन का कहना है, ओमिक्रॉन इस समय भी घातक है, इसके संक्रमण से मौत हो सकती है। मौत की दर डेल्टा से कुछ कम रह सकती है, लेकिन किसे पता है कि अगला वैरिएंट कितना घातक होगा। नए खतरनाक वैरिएंट के आने से इनकार नहीं किया जा सकता।

यूरोप में कोविड इंफेक्शन का बढ़ता ग्राफ

हालांकि ओमिक्रॉन को पहले मिले कोविड वैरिएंट्स की तुलना में कम घातक माना जा रहा है। ऐसे में महामारी के खत्म होने और जन-जीवन के सामान्य पटरी पर उतरने की उम्मीद जागी है, लेकिन यूरोप में कोरोना संक्रमण के अब तक 10 करोड़ से ज्यादा मामले आ चुके हैं। 2021 के आखिरी हफ्ते में यहां 50 लाख से अधिक केस मिले हैं। कोविड इंफेक्शन का बढ़ता ग्राफ चिंता बढ़ाने वाला है।

भारत में 2 हजार से ज्यादा ओमिक्रॉन मरीज

भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा मंगलवार को 2,000 पार पहुंच गया। अब तक देश में कुल 2,220 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं, पिछले 24 घंटे में 272 नए मामले सामने आए। ओमिक्रॉन संक्रमण देश के 24 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है।

महाराष्ट्र में नए वैरिएंट के सबसे ज्यादा 653 केस

महाराष्ट्र में नए वैरिएंट के सबसे ज्यादा 653 संक्रमित मिले हैं। दिल्ली 382 संक्रमितों के साथ दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और राजस्थान में ओमिक्रॉन के ज्यादातर केस मिले हैं।

संक्रमितों की संख्या को लेकर हालात चिंताजनक

हल्थ ऑफिसर ने कहा कि हम काफी खतरनाक फेज में हैं। पश्चिमी यूरोप में इंफेक्शन रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह कितना घातक होगा, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि, डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम है। फिर भी, संक्रमितों की संख्या को लेकर हालात चिंताजनक हैं।

ब्लैक स्पॉट में सुधार होने से दुर्घटनाएं होंगी कम: अकबर

तुंहर सरकार तुंहर द्वार: अब तक 5 लाख से अधिक आवेदकों को घर बैठे मिला लाभ

नाबालिगों द्वारा मोटरवाहन चालन पर रोक लगाने बढ़ाएं जागरूकता

परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय महानदी भवन के सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली गई। उन्होंने राज्य में बेहतर और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए संबंधित सभी उपायों पर प्रभावी अमल सुनिश्चित करने सख्त निर्देश दिए। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम सहित यातायात को बेहतर बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों के समन्वित प्रयास पर विशेष जोर दिया। परिवहन मंत्री अकबर ने बैठक में लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए गुड समैरिटन को पुरस्कृत करने अनुदान योजना-प्रत्येक नेक व्यक्ति को 5 हजार की राशि और प्रशस्ति पत्र

परिवहन मंत्री अकबर ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में चर्चा करते हुए राज्य में ब्लैक स्पॉट के चिन्हांकन पश्चात उनमें तत्परता से सुधार की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने सड़क सुरक्षा दुर्घटना को रोकने के उपायों के तहत पुलिया के दोनों ओर हैजार्ड मार्कर बोर्ड, रंबल स्ट्रीप में बार मार्किंग, स्ट्रीट लाइट तथा रोड मरम्मत कर डामरीकरण आदि के लिए भी निर्देशित किया। इसके अलावा सड़क किनारे तथा गैरेज में सुधार हेतु वाहनों की बेतरतीब पार्किंग और कंडम वाहनों के परिचालन पर रोक और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। बैठक में दुर्घटना के शिकार लोगों के त्वरित उपचार के लिए व्यवस्था, राज्य में ट्रांमा सेंटर की स्थिति, पाठ्यपुस्तकों में यातायात शिक्षा सामग्री का समावेश और यातायात के नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई और यातायात नियमों के पालन आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

परिवहन मंत्री अकबर ने सड़क सुरक्षा तथा दुर्घटना पर नियंत्रण के लिए अत्यधिक गति तथा नशे की हालात और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्ता कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। इसी तरह उन्होंने बैठक में चर्चा करते हुए सड़क निर्माण के दौरान सड़कों में अनावश्यक मोड नहीं रखने के निर्देश दिए, ताकि मोड की वजह से सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावना न हो। इस दौरान उन्होंने सड़कों के जंक्शन पर अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को रोकने के लिए पुलिस, परिवहन तथा लोक निर्माण आदि संबंधित विभागों की संयुक्त कमेटी बनाकर सघन जांच करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को वाहनों की सघन जांच और तेज गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाने की दिशा में कार्रवाई करने तथा नशापान और सड़क पर स्टंट करके वाहन चलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया। इस दौरान नाबालिग द्वारा मोटरवाहन चालन पर रोक लगाने के लिए जनजागरूकता पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने चर्चा करते हुए बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए सड़कों में हुए गड्ढों का तत्परता से मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संबंधित विभागों को सौंपे गए कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने और दूसरे घायलों के जीवन बचाने के लिए आम जनता को प्रेरित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना का संचालन प्रारंभ हो गया है। योजना का नाम ह्यमोटर गाड़ी से दुर्घटना के महत्वपूर्ण पहले घंटे के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सकीय उपचार प्रदाय करने के लिए अस्पताल अथवा आपातकालीन देख-भाल केन्द्र पहुंचाने संबंधी त्वरित व्यवस्था कर जीवन बचाने वाले नेक सहयोगी को पुरस्कृत किए जाने हेतु अनुदान योजनाह्ल है। इसके तहत प्रत्येक नेक व्यक्ति के लिए पुरस्कार की राशि 5 हजार रूपए प्रति घटना के हिसाब से निर्धारित है। साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि राज्य में वर्ष 2021 में माह जनवरी से नवम्बर तक सड़क दुर्घटना के 11 हजार 323 प्रकरणों में 9820 व्यक्ति प्रभावित हुए, जो वर्ष 2020-21 की तुलना में सड़क दुर्घटना में 8.09 प्रतिशत तथा मृत्यु में 18.29 प्रतिशत और घायल के प्रकरणों में 4.50 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई। इसे गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित विभागों को सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए समन्वित प्रयास करने विशेष जोर दिया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य में वर्ष 2020 में जनवरी से दिसम्बर तक यातायात नियमों के उल्लंघन पर कुल 3 लाख 23 हजार 649 प्रकरणों में 10 करोड़ 9 लाख 77 हजार 590 रूपए और जनवरी 2021 से नवम्बर 2021 तक 3 लाख 59 हजार 675 प्रकरणों में 10 करोड़ 40 लाख 39 हजार 550 रूपए के समन शुल्क वसूल किए गए हैं। बैठक में बताया गया कि परिवहन विभाग की ह्यतुंहर सरकार तुंहर द्वारह्ल सेवा के तहत अब तक 5 लाख से अधिक पंजीयन प्रमाण पत्र तथा चालन अनुज्ञप्ति पत्र का लाभ आवेदकों को घर बैठे मिल चुका है।

अब भूमिहीन किसानों की बारी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली किश्त का भुगतान किया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के 3 लाख 56 हजार 485 पात्र परिवार लाभान्वित होंगे। इन परिवारों को सालाना 6 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए 1 सितम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक हितग्राहियों का पंजीयन किया गया था। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन के बजट मे का प्रावधान किया गया है।

योजना से 3.56 लाख से अधिक भूमिहीन परिवार होंगे लाभान्वित

गौठानों में महिला समूहों द्वारा तैयार किये जा रहे उत्पादों की मार्केटिंग की होगी पुख्ता व्यवस्था

नामांतरण और बंटवारों के प्रकरणों का हो शीघ्र निराकरण

शहरी किरायेदारों को मिलेगा आवास

मुख्यमंत्री ने शहरी किरायेदार को भूमिस्वामी हक पर मकान उपलब्ध कराने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाई के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में निवासरत आवासहीनों को मकान मुहैया कराये जाने के उद्देश्य से प्राइवेट कालोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग इन वर्गों के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइवेट कालोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत भूमि कालोनाइजरों द्वारा नगरीय निकायों को हस्तांतरित की गई है। उन्होंने इस भूमि का लाभ कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों को की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को मार्केट से लिंकेज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ताकि उन्हें अच्छा बाजार मिले और महिलाओं की आय में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि मार्केट सर्वे कर यह जानकारी ली जाए कि बाजार में किन वस्तुओं की मांग है। मांग के आधार पर गौठानों में महिला समूहों द्वारा उत्पाद तैयार कराए जाएं। बघेल ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में महिला समूहों को सोलर पैनल तैयार करने का प्रशिक्षण देकर उनसे सोलर पैनल तैयार कराये जाएं। हालर और पेराई के लिए एक्सपेलर जैसी मशीनें अनुदान पर स्व-सहायता समूहों को उपलब्ध कराई जाए।

बघेल ने कहा कि महिला समूहों के माध्यम से कोरबा, कांकेर और कोंडागांव जिले में वनौषधियों को तैयार कराने, बीजापुर और सुकमा जिले में लघु वनोपजों के प्रसंस्करण से ऐसे उत्पाद तैयार कराए जाएं, जिनकी बाजार में अच्छी मांग है। महिला समूहों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार दिलाने के लिए संबंधित क्षेत्रों की अच्छी कंपनियों से सहयोग लिया जाए और उनके गुणवत्ता मानकों के अनुसार उत्पाद तैयार कराए जाएं। उन्होंने कहा कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को ऐसे ट्रेड में प्रशिक्षित किया जाए, जिनमें रोजगार के अच्छे अवसर हैं और जिनकी अच्छी मांग है।

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नारंगी वनों के संयुक्त सर्वे का कार्य जल्द पूरा करने और नारंगी वनों को डिनोटिफाई करने के लिए भूमि के चिन्हांकन कर राजस्व भूमि में परिवर्तित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा और इसके लिए राजस्व और वन विभाग की अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

मुर्गी पालन: महिलाओं को मिला आजीविका का नया अवसर

प्रकाश महिला स्व-सहायता समूह के लिए मुर्गीपालन आजीविका का नया अवसर लेकर आया है। समूह की 10 महिलाएं अपने घरेलू कार्य करने के बाद मुर्गीपालन व्यवसाय को अपनाकर अपने व परिवार के लिए अतिरिक्त आय अर्जित कर रही है। मुर्गीपालन से हो रहे आय को देखते हुए स्थानीय महिलाएं भी प्रेरित होकर मुर्गीपालन की ओर रूचि दिखाते हुए आजीविका के नये अवसर की ओर कदम बढ़ा रही है। विकासखण्ड सारंगढ़ के कोसीर गोठान की प्रकाश महिला स्व-सहायता समूह के सदस्यो में अनिता वनज एवं अन्य महिलाओं को मुर्गीपालन में रूचि को देखते हुए वर्ष 2020-21 में पशुधन विकास विभाग रायगढ़ द्वारा 400 नग 28 दिवसीय ब्रायलर चूजे आजीविका संवर्धन व गोठान को मल्टी-एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से प्रदाय किये गये थे। पशुधन विकास विभाग से प्राप्त चूजों का स्व-सहायता समूह के सदस्यों द्वारा गोठान में निर्मित शेड में उचित देखभाल करते हुए पालन पोषण किया गया। श्रीमती अनीता वनज एवं अन्य समूह के सदस्यों द्वारा बारी-बारी से घर के कार्यों के उपरांत बचे समय में चूजों को नियमित अंतराल में दाना एवं पानी प्रदाय किया जा रहा था। चूजों में टीकाकरण का कार्य पशु चिकित्सालय कोसीर में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा किया जाता था एवं मुर्गीपालन हेतु तकनीकी प्रशिक्षण प्रदाय किया जा रहा था। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, रायगढ़ ने समय-समय पर कोसीर गोठान का भ्रमण किया। समूह के सदस्यों को मुर्गीपालन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु उप संचालक द्वारा स्थानीय पशु चिकित्सा संस्था के अधिकारियों को निर्देशित किया गया व मुर्गीपालन हेतु तकनीकी जानकारी प्रदाय की गई। लगभग 45 दिवस में अधिकांश चूजों का वजन 1.5 कि.ग्रा.तक पहुंचने लगा एवं मुर्गो को वजन के हिसाब से स्व-सहायता समूह के सदस्यों द्वारा विक्रय स्थानीय बाजार में 100 रुपये किलो ग्राम की दर से किया गया। इस प्रकार समस्त मूर्गो के लगभग 1.5 किलो ग्राम वजन प्राप्त करने के उपरांत विक्रय स्व-सहायता समूह के सदस्यों द्वारा स्थानीय बाजार में विक्रय किया गया। विक्रय करने पर समूह के सदस्यों को लगभग 52 हजार 500 रुपये की आय अर्जित की गई। मुर्गीपालन में समस्त लागत व्यय पश्चात स्व-सहायता समूह के सदस्यों को 16 हजार 500 रुपये शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। जिससे समूह की महिलाओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शासन-प्रशासन को धन्यवाद दिया है तथा काम को आगे विस्तार दे रही है।

“1 जनवरी 2022 को फोन का रिचार्ज कराया जाए और 31 दिसंबर 2022 तक फुर्सत हो जाए। तो सोचिए कैसा रहेगा? यानी साल के 365 दिन कोई नया रिचार्ज कराने की जरूरत न पड़े। रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया (वी) जैसी सभी कंपनियों के पास ऐसे प्लान मौजूद हैं। सालभर की वैलिडिटी वाले इन सिंगल रिचार्ज पर अच्छे-खासे रुपए भी बच जाते हैं।”

नए साल में रिचार्ज के फायदे इतने की बचत

हम आपको इन सभी कंपनियों के ऐसे ही डेटा प्लान के बारे में बता रहे हैं। सालभर वाले डेटा प्लान से न सिर्फ बार-बार फोन रिचार्ज कराने का झंझट खत्म होता है, बल्कि इससे दो रिचार्ज तक के पैसे भी बच जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सालभर वाले रिचार्ज का अमाउंट बार-बार रिचार्ज कराने वाले प्लान से औसतन कम होता है। वहीं, हर महीने वाले प्लान की वैलिडिटी 28 दिन, 56 दिन या 84 दिन होती है। 28 दिन की वैलिडिटी वाले 13 रिचार्ज कराने पर 364 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इसी तरह 56 दिन और 84 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान में भी 28 दिन की वैलिडिटी वाला एक्स्ट्रा रिचार्ज कराना होता है। कुल मिलाकर एक रिचार्ज के एक्स्ट्रा रुपए खर्च करने पड़ते हैं।

अब बात करते हैं कि सालाना प्लान में आपको फायदा कैसे मिलेगा?

सालभर वाले रिचार्ज में रिलायंस जियो ग्राहकों का फायदा

जियो के पास देशभर में करीब 44 करोड़ ग्राहक हैं। सभी ग्राहक अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से रिचार्ज भी कराते होंगे। जियो के पास 14 दिन की वैलिडिटी के साथ 365 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान मौजूद हैं। सभी पर अलग-अलग डेटा मिलता है। हालांकि, सालाना रिचार्ज पर मिलने वाले फायदा दूसरे सभी प्लान की तुलना में ज्यादा है। जियो के पास सालभर की वैलिडिटी वाले अभी 4 प्लान हैं। इनमें 2545 रुपए, 2879 रुपए, 3119 रुपए और 4199 रुपए वाले प्लान शामिल हैं। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

यदि ग्राहक डेली 1.5GB डेटा प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ लेता है तब उसे सालभर में 13 रिचार्ज कराना होंगे। इस प्लान की कीमत 239 रुपए है। यानी 13 रिचार्ज के लिए उसे 3107 रुपए खर्च करने होंगे। जबकि सालभर वाले प्लान में उसको 2545 रुपए ही खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी 562 रुपए की बचत हो रही है।

अब यदि ग्राहक डेली 2GB डेटा प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ लेता है तब उसे सालभर में 13 रिचार्ज कराना होंगे। इस प्लान की कीमत 299 रुपए है। यानी 13 रिचार्ज के लिए उसे 3887 रुपए खर्च करने होंगे। जबकि सालभर वाले प्लान में उसको 2879 रुपए ही खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी 1,008 रुपए की बचत हो रही है।

इसी तरह यदि ग्राहक डेली 3GB डेटा प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ लेता है तब उसे सालभर में 13 रिचार्ज कराना होंगे। इस प्लान की कीमत 419 रुपए है। यानी 13 रिचार्ज के लिए उसे 5447 रुपए खर्च करने होंगे। जबकि सालभर वाले प्लान में उसको 4199 रुपए ही खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी 1248 रुपए की बचत हो रही है।

सालभर वाले रिचार्ज में भारती एयरटेल ग्राहकों का फायदा

भारती एयरटेल देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी है। देशभर में उसके पास 35 करोड़ यूजर हैं। कंपनी के पास 365 दिन की वैलिडिटी वाले 3 प्लान मौजूद हैं। इनमें 1799 रुपए, 2999 रुपए और 3359 रुपए वाले प्लान शामिल हैं। सभी प्लान पर कंपनी अलग-अलग सुविधाएं दे रही है। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

यदि ग्राहक कुल 2GB डेटा प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ लेता है तब उसे सालभर में 13 रिचार्ज कराना होंगे। इस प्लान की कीमत 179 रुपए है। यानी 13 रिचार्ज के लिए उसे 2327 रुपए खर्च करने होंगे। जबकि सालभर वाले प्लान में उसको 1799 रुपए ही खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी 528 रुपए की बचत हो रही है।

अब यदि ग्राहक डेली 2GB डेटा प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ लेता है तब उसे सालभर में 13 रिचार्ज कराना होंगे। इस प्लान की कीमत 359 रुपए है। यानी 13 रिचार्ज के लिए उसे 4667 रुपए खर्च करने होंगे। जबकि सालभर वाले प्लान में उसको 2999 रुपए ही खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी 1668 रुपए की बचत हो रही है।

सालभर वाले रिचार्ज में वोडाफोन आइडिया (Vi) ग्राहकों का फायदा

वोडाफोन आइडिया (Vi) के पास देशभर में 27 करोड़ यूजर हैं। जियो और एयरटेल के बाद ये देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी भी है। वीआई के पास 365 दिन की वैलिडिटी वाले कुल 3 प्लान हैं। इसमें 1799 रुपे, 2899 रुपए और 3099 रुपए वाले डेटा प्लान शामिल हैं। सभी प्लान पर कंपनी अलग-अलग सुविधाएं दे रही है। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

यदि ग्राहक कुल 2GB डेटा प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ लेता है तब उसे सालभर में 13 रिचार्ज कराना होंगे। इस प्लान की कीमत 179 रुपए है। यानी 13 रिचार्ज के लिए उसे 2327 रुपए खर्च करने होंगे। जबकि सालभर वाले प्लान में उसको 1799 रुपए ही खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी 528 रुपए की बचत हो रही है।

अब यदि ग्राहक डेली 1.5GB डेटा प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ लेता है तब उसे सालभर में 13 रिचार्ज कराना होंगे। इस प्लान की कीमत 299 रुपए है। यानी 13 रिचार्ज के लिए उसे 3887 रुपए खर्च करने होंगे। जबकि सालभर वाले प्लान में उसको 2899 रुपए ही खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी 988 रुपए की बचत हो रही है।

अब यदि ग्राहक डेली 1.5GB डेटा प्लान 56 दिन की वैलिडिटी के साथ लेता है, जिसमें उसे डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, तब उसे सालभर में 6 रिचार्ज के साथ एक 28 दिन की वैलिडिटी वाला रिचार्ज भी कराना होगा। 56 दिन वैलिडिटी वाले प्लान की कीमत 479 रुपए है। यानी 6 रिचार्ज के लिए उसे 2874 रुपए के साथ 299 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। इस तरह उसे कुल 3173 रुपए खर्च करने होंगे। जबकि सालभर वाले प्लान में उसको 3099 रुपए ही खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी 74 रुपए की बचत हो रही है।

साल 2022 में इन तीनों हीरों की आ रही फिल्म

> साल 2022 के दस्तक देते ही 2021 ढल गया और अब भारतीय फि ल्म इंडस्ट्री में भी आशाओं की नई किरण का उदय हो रहा है. कोरोना महामारी के चलते साल 2021 के अधिकांश महीने सिनेमाघर बंद रहे. फि लहाल इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर का खतरा जरूर दिख रहा है, लेकिन जानकार इसे डेल्टा के मुकाबले कम खतरनाक मान रहे हैं.

बॉलीवुड

इसी उम्मीद के सहारे हिंदी फि ल्म इंडस्ट्री भी धीरे-धीरे अपनी रफ़्तार पकड़ने की कोशिश में लगी है. इस साल कई फि ल्में रिलीज की कगार पर खड़ी हैं. चलिए हम आपको उन बड़ी फि ल्मों के बारे में बताते हैं, जिनके रिलीज होने का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. शुरूआत करते हैं सुपरस्टार्स की फि ल्मों से.चार साल बाद पर्दे पर दिखेंगे आमिर खान

करीब चार साल के अंतराल के बाद आमिर खान अपनी नई फि ल्म ह्यलाल सिंह चड्ढाह्न लेकर आ रहे हैं, जो हॉलीवुड फि ल्म ह्यफॉरेस्ट गंपह्न का भारतीय रूपांतरण है.फि ल्म में आमिर खान सिख व्यक्ति के किरदार में दिखेंगे. कोरोना महामारी के कारण फि ल्म की रिलीज में एक साल की देरी हो गई है. अद्वैत चंदन निर्देशित लाल सिंह चड्ढा में करीना कपूर भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. फि ल्म 14 अप्रैल, 2022 को रिलीज होगी.

राजामौली की आर आर आर में अजय देवगन

बाहुबली की अपार सफलता के बाद निर्देशक एस एस राजामौली अपनी अगली फि ल्म ह्यआर आर आरह्न लेकर आ रहे है. इसमें जूनियर एनटीआर, रामचरण, आलिया भट्ट और अजय देवगन प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे. ये पैन इंडिया फि ल्म साल के पहले शुक्रवार में रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के कारण इसकी रिलीज टाल दी गई है. हालांकि फि ल्म कौन-सी तारीख को रिलीज होगी इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है. वहीं अजय देवगन की स्पोट्र्स ड्रामा ह्यमैदानह्न 3 जून, 2022 को रिलीज होगी. अजय देवगन की इंद्रकुमार निर्देशित फि ल्म ह्यथैंक गॉडह्न 29 जुलाई, 2022 को रिलीज होने वाली है. इस फि ल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत उनका साथ देते नजर आएंगी.

अमिताभ बच्चन भी कई फिल्मों में दिखेंगे सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन अभी भी इंडस्ट्री के सबसे व्यस्ततम कलाकारों में से एक हैं. उनकी कई फिल्में इस साल रिलीज होंगी. उनमें बहुचर्चित साइंस फिक्शन फिल्म ह्वब्रह्मास्त्रह्व भी शामिल है, जिसमें वे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे. ये फिल्म 9 सितम्बर, 2022 को रिलीज होगी. मराठी फिल्म ह्वसैराटह्व से चर्चा में आए निर्देशक नागराज मंजुले के साथ अमिताभ बच्चन ह्वझुंडह्व में दिखेंगे. ह्वक्वीनह्व से चर्चा में आए निर्देशक विकास बहल की अगली फिल्म ह्वगुडबायह्व में अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता के साथ नजर आएंगे. दोनों फिल्मों की रिलीज डेट की घोषणा फिलहाल नहीं हुई है. अजय देवगन के साथ अमिताभ एक बार फिर बड़े पर्दे पर दिखेंगे फिल्म ह्वरनवे 34ह्व में, जो 29 अप्रैल को रिलीज होगी.

महिला प्रधान फिल्में

2022 में कई महिला प्रधान फिल्में आ रही हैं, जिसमें दिलचस्प कहानी और अभिनय की उम्मीद की जा सकती है. इनमें कंगना रनौत की फिल्म ह्वतेजसह्व एक साहसी महिला फाइटर पायलट की कहानी है.

यह भारतीय वायुसेना से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना से प्रेरित फिल्म है, जो महिलाओं को लड़ाकू विमान चलाने की भूमिका में दिखाती है. यह फिल्म 5 अक्तूबर, 2022 को रिलीज होगी. इस साल तापसी पन्नू दो महिला प्रधान फिल्मों में नजर आएंगी. इसमें से एक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज पर आधारित ह्वशाबाश मिठूह्व है, जो 4 फरवरी, 2020 को रिलीज होगी. दूसरी, तापसी की होम प्रोडक्शन फिल्म ह्वब्लर्रह्व है जिसकी रिलीज की घोषणा भी जल्द की जाएगी. संजय लीला भंसाली की अगली पेशकश ह्वगंगूबाई काठियावाड़ीह्व में आलिया भट्ट मुंबई के 60 के दशक की तवायफ के रूप में नजर आएंगी. यह फिल्म 18 फरवरी, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं, रानी मुखर्जी, आशिमा छिब्बर की फिल्म ह्वमिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वेह्व में दिखेंगी. यह फिल्म 2011 के नॉर्वे के मशहूर केस पर आधारित है, जिसमें नॉर्वे में रह रहे भारतीय जोड़ों से उनके बच्चों को अलग कर दिया जाता है. फिल्म 20 मई, 2022 को रिलीज होगी.

सीक्वल की लगी हैकतार

2022 में कई सीक्वल भी नजर आएंगे, जिसमें अक्षय कुमार की ह्वओ माय गॉड 2ह्व और कार्तिक आर्यन की फिल्म ह्वभूल भुलैया 2ह्व प्रमुख हैं. भूलभुलैया 2 में कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. यह फिल्म 25 मार्च को रिलीज होगी. अनिल शर्मा की साल 2000 की हिट फिल्म का सीक्वल ह्वगदर 2ह्व भी इस साल रिलीज होने वाली है. इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक साथ नजर आएंगे. ह्वबधाई दोह्व 2018 की फिल्म ह्वबधाई होह्व का सीक्वल है. ये एक पारिवारिक ड्रामा है जिसमें भूमि पेडनेकर और राजकुमार राव ने अभिनय किया है. फिल्म 4 फरवरी को रिलीज होने वाली है. टाइगर श्रॉफ की ह्वहीरोपंती 2ह्व एक्शन रोमांटिक एक्शन फिल्म है और 2014 की फिल्म ह्वहीरोपंतीह्व की अगली कड़ी है. इसमें टाइगर श्रॉफ के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी अहम भूमिका में नजर आएंगे.

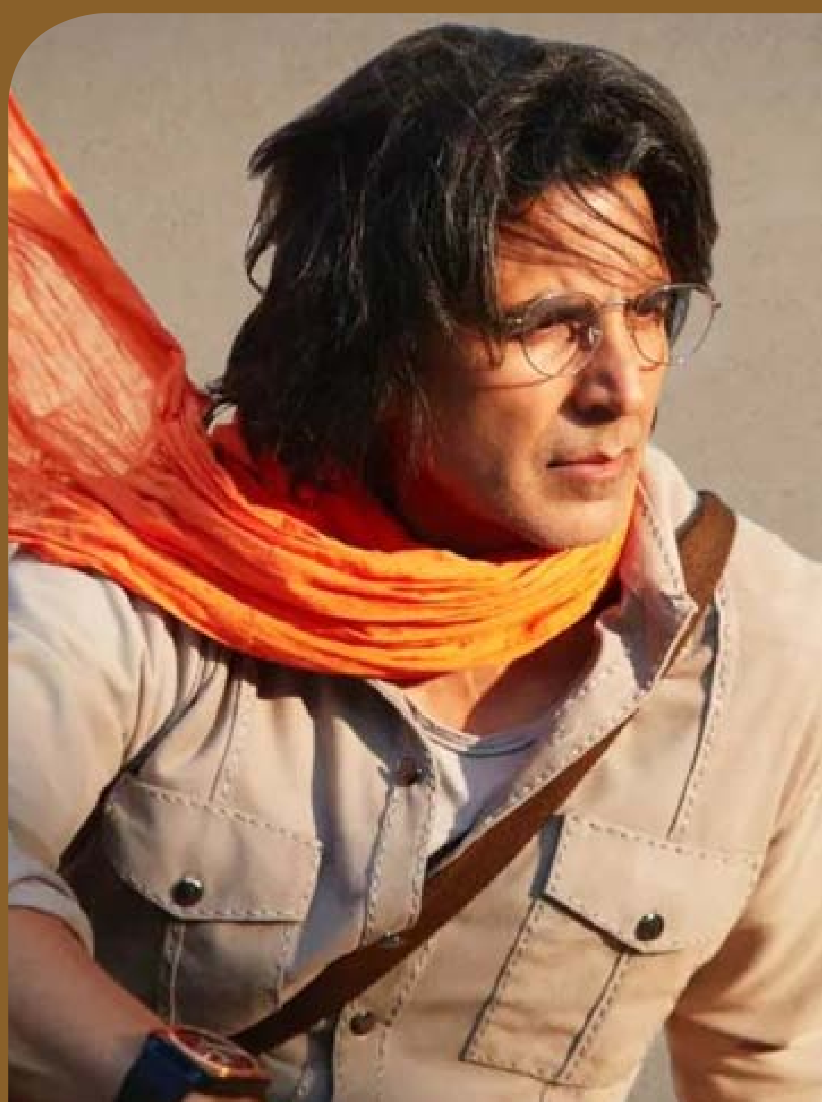

अक्षय कुमार लगाएंगे फिल्मों का चौका

हर साल चार फिल्में लाने वाले अक्षय कुमार 2022 में भी चार फिल्मों के साथ तैयार हैं. इनमें ऐतिहासिक किरदारों पर आधारित ह्वपृथ्वीराज चौहानह्व 21 जनवरी, 2022 को रिलीज होगी. निर्देशक आनंद एल राय के साथ अक्षय कुमार की फिल्म ह्वरक्षाबंधनह्व 11 अगस्त, 2022 में रिलीज होगी. दिवाली पर अक्षय कुमार की बहुचर्चित फिल्म ह्वरामसेतुह्व रिलीज होगी, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरुचा उनके साथ नजर आएंगी. अक्षय की चौथी फिल्म ह्वओ माइ गॉड 2ह्व होगी, जो ह्वओ माय गॉडह्व का सीक्वल है. इसमें पंकज त्रिपाठी अहम भूमिका में नजर आएंगे.

ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म

2020 में दुनिया को अलविदा कह चुके अभिनेता ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म ह्वशमार्जी नमकीनह्व भी 2022 में रिलीज होने वाली है. निर्देशक हितेश भाटिया निर्देशित इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ जूही चावला और परेश रावल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे.

पैन इंडिया फिल्में और हीरो

बाहुबली की सफलता के बाद पैन इंडिया फिल्मों में दर्शकों की रुचि बढ़ी है. कई दक्षिण भारतीय अभिनेताओं की फिल्मों को बड़ी रिलीज मिल रही है. ह्वबाहुबलीह्व से ख्याति प्राप्त अभिनेता प्रभास की अगली पैन इंडिया फिल्म ह्वराधे श्यामह्व एक रोमांटिक ड्रामा है. ये फिल्म 14 जनवरी को रिलीज होगी.कन्नड़ स्टार यश की पैन इंडिया फिल्म ह्वकेजीएफह्व के दूसरे भाग को 14 अप्रैल, 2022 को रिलीज के लिए तय किया गया है. इसमें संजय दत्त और रवीना टंडन भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. दक्षिण भारत के ह्वकबीर सिंहह्व माने जाने वाले विजय डेवेराकोंडा हिंदी फिल्मों में अपनी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं. फिल्म ह्वलिगरह्व में वे अमेरिकी बॉक्सर माइक टाइसन के साथ लड़ते दिखेंगे. यह फिल्म 25 अगस्त, 2022 को रिलीज होगी.वहीं दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता विजय सेतुपति भी हिंदी फिल्म में ह्वमेरी क्रिसमसह्व से अपनी पारी शुरू करने जा रहे हैं. इस फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन करेंगे. उनके साथ कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में होंगी. फिल्म 23 दिसंबर, 2022 को रिलीज होगी.

विवेक अग्निहोत्री निर्देशित ह्वकश्मीर फाइल्सह्व 26 जनवरी, 2022 को रिलीज होगी. इसकी कहानी कश्मीरी हिन्दुओं के पलायन पर बनाई गई है.

नई पीढ़ी, नई कहानी

83 में कमाल का अभिनय देने वाले रणवीर सिंह इस साल गुजराती अवतार में नजर आएंगे. फिल्म का नाम है ह्वजयेशभाई जोरदार,ह्व जो 25 फरवरी, 2022 को रिलीज होगी. वहीं, ह्वसिम्बाह्व के बाद रणवीर सिंह एक बार फिर निर्देशक रोहित शेट्टी के साथ हाथ मिलाते दिखेंगे. इस बार वो उनके निर्देशन में फिल्म ह्वसर्कसह्व कर रहे हैं. रणबीर कपूर यशराज की एक्शन फिल्म ह्वशमशेराह्व में नजर आएंगे. फिल्म 18 मार्च को रिलीज होगी. अलग-अलग और लीक से हटकर विषयों के चयन के लिए जाने वाले आयुष्मान खुराना नजर फिल्म ह्वडॉक्टर जीह्व में आएंगे, जो एक सोशल ड्रामा है. कार्तिक आर्यन, हंसल मेहता की फिल्म ह्वकैप्टेन इंडियाह्व में नजर आएंगे. सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म 2015 के युद्धग्रस्त यमन के दौरान एयर इंडिया के एक पायलट की कहानी है. इस कहानी में भारत के सबसे बड़े बचाव अभियान में से एक ह्वऑपरेशन राहतह्व का चेहरा बन जाते हैं. वहीं वरुण धवन, अमर कौशिक की फिल्म ह्वभेड़ियाह्व में नजर आएंगे. 2021 में लोगों पर अपनी छाप छोड़ने वाली कियारा आडवाणी, वरुण धवन के साथ धर्मा फिल्म की ह्वजुग जुग जियोह्व में दिखेंगी. इस फिल्म में अनिल कपूर और नीतू कपूर भी नजर आएंगी. फिल्म 24 जून को रिलीज होगी. कैटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ हॉरर कॉमेडी ह्वफोन भूतह्व में नजर आएंगी, जो 15 जुलाई को रिलीज हो रही है.वहीं सिद्धांत चतुर्वेदी, दीपिका पादुकोण के साथ शकुन बत्रा की फिल्म ह्वगहराइयाँह्व में भी नजर आएंगे. यह फिल्म ओटीटी पर 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. टाइगर श्रॉफ अपनी एक्शन छवि को बरकरार रखते हुए विकास बहल की ह्वगणपत- पार्ट 1ह्व में दिखाई देंगे. वहीं सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म ह्वपठानह्व और सलमान खान की फिल्म ह्वएक था टाइगर 3ह्व की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है. हालांकि ये दोनों क्या इस साल रिलीज होंगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है. यशराज फिल्म की ओर से इन फिल्मों की रिलीज की तारीख अभी तय नहीं की गई है.

माह : जनवरी 2022

राशिफल

मेष

व्यवसाय में भाग्य का साथ मिलेगा और धन लाभ के योग बनेंगे। नए क्षेत्रों में निवेश करने से आपको इस वर्ष लाभ हो सकता है। व्यवसाय के संबंध में नए विचारों में आपकी रुचि हो सकती है। इस वर्ष विदेश यात्रा का भी मौका हासिल हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति के योग की प्रबल संभावनाएं इस वर्ष बनने और कार्य में सक्रियता और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का सबसे शुभ समय मध्य मई से अक्टूबर तक का होगा।

वृष

यह वर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए एक अच्छा वर्ष होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बृहस्पति साल के अधिकांश समय आपके दसवें भाव में रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपने कार्यस्थल में बहुत लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित हैं तो भी आप बेहतर लाभ कमाएंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी इस दौरान करियर में आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से या वर्ष काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।

मिथुन

इस साल आपको करियर के क्षेत्र में कई अवसर मिल सकते हैं। अवसरों का लाभ उठाने से पहले खुद पर ध्यान दें और अपने काम पर फोकस करें। व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े जातक इस वर्ष बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। यदि मिथुन राशि के जातक किसी नई व्यावसायिक परियोजनाओं को लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप वर्ष के दूसरे भाग में इस परियोजना पर काम करें।

कर्क

करियर के हिसाब से यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में उन्नति व प्रगति प्राप्त होगी आप अपने प्रयासों से उन्नति प्राप्त करेंगे। आपकी नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष की शुरूआत इतनी अनुकूल नहीं होगी और सफलता हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और ध्यान एकाग्र करना पड़ सकता है।

सिंह

वर्ष की शुरूआत बहुत अच्छी रहेगी। इस दौरान आप अपने कार्य के प्रति अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। मई के पश्चात आप कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपको वांछित लाभ प्राप्त होगा और आप अपने व्यवसाय से संतुष्ट रहने वाले हैं। जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं उन्हें कार्यस्थल पर अधिक मान सम्मान मिलेगा।

कन्या

करियर के लिहाज से कन्या राशि वालों के लिए जनवरी मार्च और जून के महीने काफी बेहतर रहेंगे और मई के शुरूआत में कुछ लोगों को मनचाहा स्थानांतरण भी मिल सकता है। नौकरीपेशा जातक पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं जो जातक उद्योग के काम को बदलने की योजना बना रहे थे वो इसे बेहतर करने में सक्षम हो सकते हैं। जो लोग वर्तमान में बेरोजगार हैं उन्हें इस वर्ष नौकरी मिल सकती है।

तुला

इस वर्ष आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी अन्यथा कोई रोग आपको परेशान कर सकता है ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही हर प्रकार की छोटी-मोटी समस्याओं से अपने शरीर का बचाव करें मौसम के बदलाव से पैदा होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क रहें। वर्ष के शुरूआत आपके आर्थिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल से सितंबर तक का समय आपको धन लाभ की प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम कहा जाएगा।

वृश्चिक

वृश्चिक जातकों को कुछ चुनौतियों से इस वर्ष परिवारिक जीवन में गुजारना पड़ सकता है क्योंकि ग्रहों की दृष्टि आपके परिवारिक जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली है। आप अपनी एकाग्रता, प्रयास और कड़ी मेहनत के दम पर इस वर्ष अपने करियर में सफल हो सकते हैं। अप्रैल के बाद जब बृहस्पति पांचवें भाव में गोचर करेगा, तब आपकी स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है।

धनु

इस वर्ष आपको कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। अप्रैल महीने के बाद स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो सकता है। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए सितंबर के बाद का महीना सकारात्मक रहने की उम्मीद है। इसके अलावा नवंबर माह में आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी विदेश यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है।

मकर

साल 2022 में मकर राशि वाले जातकों कार्यक्षेत्र में विशेष मेहनत करने की जरूरत होगी। इस दौरान आपको मेहनत के अनुसार अच्छे और बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आप नौकरी, कार्यक्षेत्र या फिर कंपनी बदलने के इच्छुक हैं तो इस कार्य को साल के पहली या अंतिम तिमाही में करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। आप अपने सहयोगियों और वरिष्ठों से इस वर्ष अच्छे संबंध बना कर रखें।

कुम्भ

इस वर्ष कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नौकरी या व्यापार में परिवर्तन के लिए अप्रैल और मई का महीना सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाला है। साल के उत्तरार्ध में आपको कुछ समस्या हो सकती है। साढ़ेसाती होने की वजह से कोई भी कार्य शुरू करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें, इससे आपके व्यवसाय में तरक्की होने की संभावना में वृद्धि होगी। साल की अंतिम तिमाही कुंभ राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से बेहतर रहने की संभावना है।

मीन

आप इस समय अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिससे आप इस वर्ष एक बेहतर करियर का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप इस वर्ष कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि अप्रैल महीने में इसकी शुरूआत करें क्योंकि इस अवधि में आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक है।

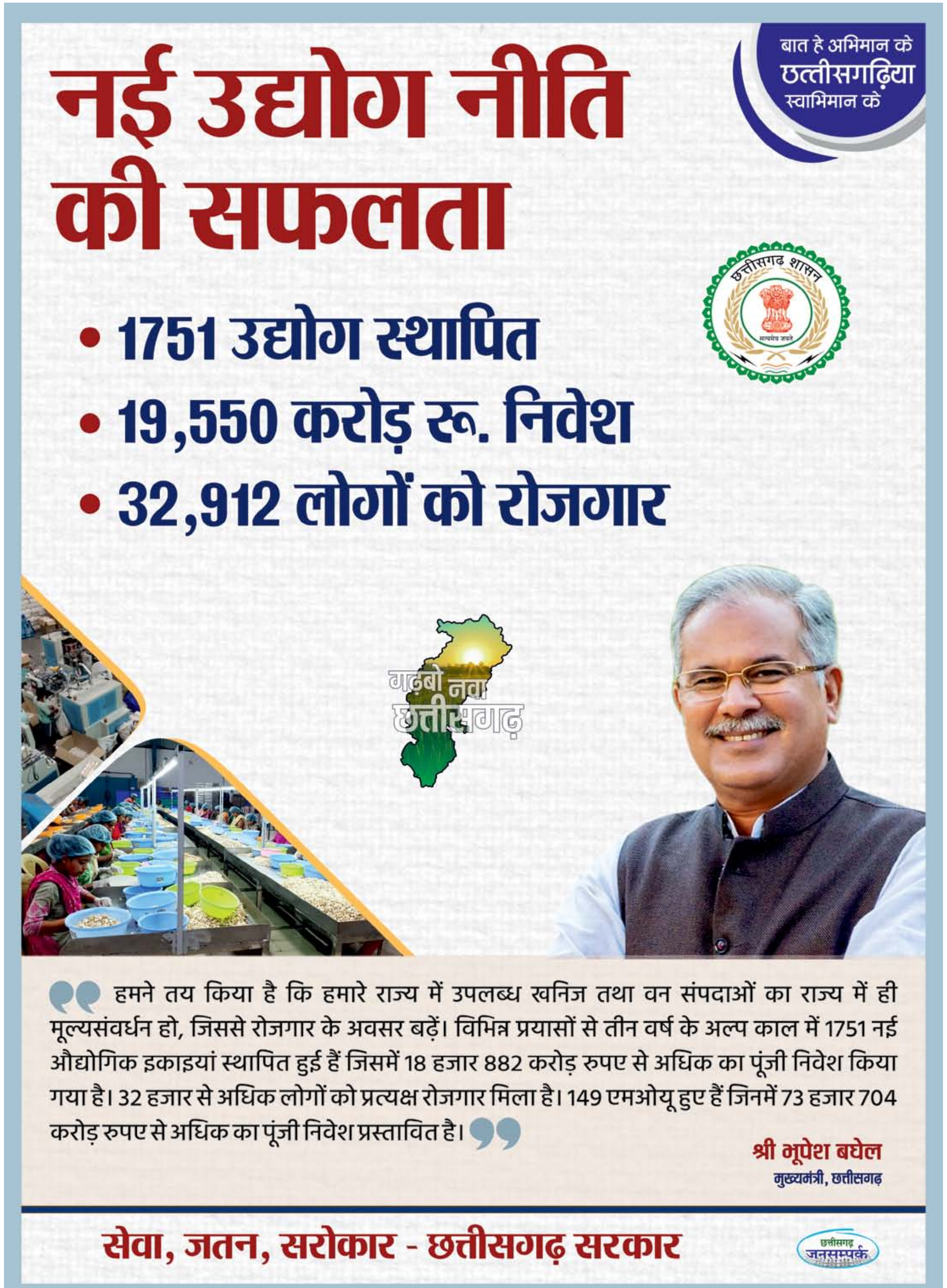

R.O NO - 11691/78